अरुण कुमार और अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

15 सितंबर 2006

[वाई.के. सभरवाल। सी जे। सी.के. ठक्करंद, पी. के. बालासुब्रमणि जे. जे.]

*आयकर अधिनियम 1962- नियम 3- आयकर अधिनियम 1961–धारा 1-12- .परिशिष्टों का मूल्यांकन करने की विधि- संशोधन-कर्मचारियों के बीच वर्गीकरण, सरकारी और कंपनी कर्मचारियों. अन्य उपक्रम के संबंध में नियोक्ताओं-वैधता- आयोजित - वर्गीकरण उचित है जो बोधगम्य विभेदों पर आधारित होता है- तर्कसंगत संबंध उस वस्तु के लिए जिसे उसने प्राप्त किया है-यह न तो मनमाना, भेदभावपूर्ण,या **अधिकारातीत** है, अनुच्छेद 14 के तहत और न ही अधिनियम की धारा 17 (2)(ii) के साथ असंगत है -- नियम 3 केवल आवास के संबंध मे किराये के मामले मे नियोजित द्वारा अपने कर्मचारियों को दिखाई गई 'रियायत' के मामलों पर लागू होता है--रियायत के बारे में 'काल्पनिक मान्यता' बनाने का कोई प्रावधान नहीं है- इस प्रकार निर्धारिती यह कह सकता है की आवास के संबंध मे किराये के मामले मे कोई रियायत नही है और यह मामला धारा 17(2)(ii) के अंतर्गत नही आता है- भारत का संविधान 1950- अनुच्छेद 14.*

*क्षेत्राधिकार: क्षेत्राधिकार तथ्य- का अस्तित्व - क्या न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए **अनिवार्य रूप** से गैर-या शर्त पूर्ववर्ती है-यदि क्षेत्राधिकार तथ्य मौजूद है, तो प्राधिकरण के अनुसार उचित निर्णय ले सकता है, जो 'मुद्दे में तथ्य' का या 'न्यायिक तथ्य' का फैसला कर सकता है' ।*

सिद्धांत/सिद्धांत: 'नीचे पढ़ने' का सिद्धांत-कानून की वैधता को बनाए रखने के लिए इसका अनुप्रयोग-समझाया गया।

**एक अधिसूचना द्वारा, आयकर नियम, 1962 के नियम 3 में संशोधन किया गया था और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के तहत नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान किए गए किराए के आवास के मामले में अनुलाभ के मूल्यांकन की गणना की विधि को संशोधित किया गया था। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित कर्मचारियों के संबंध में, आवास से संबंधित परिलब्धियों का मूल्यांकन 4 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में वेतन का 10 प्रतिशत अथवा चार लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में वेतन का 75 प्रतिशत होगा। और अपीलकर्ता- निजी क्षेत्र के एक कर्मचारी ने नियमों के नियम 3 की वैधता को चुनौती दी। यह तर्क दिया गया था कि संशोधित नियम 3 ने राजस्व पर मनमानी और निरंकुश शक्तियां प्रदान कीं; कि यह मूल अधिनियम के साथ असंगत था; और यह कि गणना-विधि न तो बोधगम्य विभेद पर आधारित थी और न ही प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध था, इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय ने माना कि जनसंख्या के संबंध में शहरों के बीच वर्गीकरण उचित और तर्कसंगत था, और इस प्रकार, नियम 3 को बरकरार रखा।**

**एक अन्य उच्च न्यायालय के समक्ष इसी तरह के एक मुद्दे में, नियम 3 की वैधता को बरकरार रखा गया था कि नियम ने किराए के मामले में रियायत के मूल्य का पता लगाने की विधि और आधार तैयार किया था जिसे मनमाना या *अधिकारातीत* नहीं ठहराया जा सकता था; और यह कि सरकारी कर्मचारियों और कंपनियों, निगमों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के बीच वर्गीकरण उचित था और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं था। इसलिए वर्तमान मायने रखता है।**

**आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए और स्थानांतरण मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय**

**आयोजित:1. किसी क़ानून की वैधता पर विचार करते समय यह धारणा हमेशा संवैधानिकता के पक्ष में होती है और यह भार उस व्यक्ति पर होता है जो यह दिखाने के लिए उस पर हमला करता है कि संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। किसी अधिनियम की संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए, एक अदालत सामान्य ज्ञान, अभिलेख,**

**प्रस्तावना, समय के इतिहास, कानून के उद्देश्य और अन्य सभी तथ्यों के मामलों को ध्यान में रख सकती है जो प्रासंगिक हैं। यह हमेशा माना जाना चाहिए कि विधायिका अपने लोगों की जरूरतों को समझती है और सही ढंग से सराहना करती है और यह भेदभाव, यदि कोई हो, पर्याप्त आधार और विचारों पर आधारित है। यह भी सुस्थापित है कि संवैधानिक अमान्यता से बचने के लिए न्यायालयों द्वारा उदार व्याख्या करना न्यायोचित होगा। प्राधिकरण को बहुत व्यापक और व्यापक शक्तियां प्रदान करने वाले प्रावधान को संवैधानिक सीमाओं के भीतर शक्ति के प्रयोग के विधायी इरादे के अनुरूप माना जा सकता है। जहां एक क़ानून चुप है या अस्पष्ट है, अदालत अव्यक्त को प्रसारित करने और एक निर्माण को अपनाने का प्रयास करेगी जो संवैधानिकता की ओर झुकेगी, *हालांकि* उस सामग्री से प्रस्थान किए बिना जिसमें कानून बुना गया है। इन सिद्धांतों ने प्रावधानों को 'पढ़ने' के नियम को जन्म दिया है यदि कानून की वैधता को बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। लेकिन अगर कानून का प्रावधान स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, भाषा स्पष्ट है और व्याख्या एक से अधिक निर्माण के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है, तो इसे वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसा कि यह है। उस मामले में, कानून के प्रावधान के तहत दायर किया जाना चाहिए। विधि अथवा संविधान के संगत उपबंधों की कसौटी पर परीक्षण किया जाना चाहिए और यह न्यायालय के लिए खुला नहीं है कि वह संविधि को *अधिकारातीत* घोषित करने से बचाने के उद्देश्य से इसे संविधि के प्रयोजनों को विकृत करने के बिन्दु तक ले जाने से इसे अधिकारातीत घोषित करने से बचाए रखने के लिए पठन के सिद्धांत को लागू करे।**

**[315-बीएफ; 316-जीएच; 317-ए-बीआई]**

*बिक्री कर आयुक्त, मध्य प्रदेश और अन्य बनाम राधाकृष्णन और अन्य* **[1979] 2 एससीसी 249;** *ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम* **[1985] 3 एससीसी 545**; सलेम एडवोकेट बार संघ बनाम भारत संघ **[2005] 6 SCC 344**; *मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ,* **[1980] 3 एससीसी 625** और *दिल्ली परिवहन निगम बनाम डीटीसी मजदूर कांग्रेस और अन्य,***[1991] आईसी पूरक एससीसी 600**, **पर भरोसा किया।**

कॉलिन हॉवर्ड द्वारा "*ऑस्ट्रेलियाई संघीय संवैधानिक कानून*", **संदर्भित।**

**2.1. आयकर नियम, 1962 के नियम 3 में इसके संशोधन से पहले चर्चा की गई थी की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए रियायत की गणना की विधि के साथ "उचित किराया मूल्य"। नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने निर्धारिती को यह संतुष्ट करने का अवसर प्रदान किया कि किराया वसूल किया जाना चाहिए। कर्मचारी से 'रियायत' नहीं कहा जा सकता था क्योंकि यह 'उचित किराया' था। ' उचित किराया ',' बाजार किराया 'या' मानक किराया 'और इसलिए नहीं हो सकता है आयकर की खंड 17 (2) (ii) के अर्थ के भीतर शर्त कहा जाता है। अधिनियम, 1961। नियमों के संशोधित नियम 3 में "उचित किराये के मूल्य" की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। जब "उचित किराया" की अवधारणा, "बाजार" किराया "," उचित किराया "या" मानक किराया "अब प्रासंगिक या सामान्य नहीं है।प्रश्न का निर्णय लेने में, यह विधानमंडल के लिए खुला था कि वह नियम को सशक्त करे "रियायत" की गणना के लिए विधि प्रदान करने का अधिकार देना एकमात्र तरीका जो अपनाया गया है वह है किराए की गणना करना जिसके आधार पर विचाराधीन शहर की जनसंख्या जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।**

**[318 - सी-ई; 319-एफ-एच]**

**2.2 . यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण का इरादा निर्धारिती को निर्धारण अधिकारी को यह समझाने का अवसर देना था कि नियोक्ता**

**द्वारा अपने कर्मचारी से वसूल किया गया किराया इस मामले में नहीं था। रियायत की प्रकृति। न ही कोई न्यायालय, व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा, निर्धारिती को ऐसा अवसर प्रदान करेगा ताकि वह निर्धारण अधिकारी को यह समझाने में सक्षम हो कि निर्धारित किराया अधिनियम की खंड 17 (2) (ii) के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए यह 'शर्त' नहीं है। [ 318 - ई-जी]**

**2.3 . यह कहा नहीं जा सकता है कि खंड 17 (2) केवल तभी लागू होगी जब 'अनुलाभ' हो।'शर्त' में किराया-मुक्त आवास का मूल्य शामिल है- निर्धारिती को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया; किसी भी रियायत का मूल्य किसी भी आवास के संबंध में किराए का मामला।'अनिवार्यता' की परिभाषा समावेशी प्रकृति की है और नहीं।यह खंड (i) से खंड (vii) में वर्णित कई मामलों को अपने दायरे में लेता है। ' इस प्रकार 'शर्त' नियमित**

**वेतन या मजदूरी के अलावा किसी रोजगार के लिए एक विशेषाधिकार, लाभ या लाभ है। खंड 17 (2) (ii) घोषित करती है कि कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले मेंकिसी भी "रियायत" का मूल्य "आवश्यक" होगा। फिर भी यह नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को प्रदान किए गए किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में एक "*रियायत*" होनी चाहिए। "रियायत" शब्द को न तो अधिनियम में परिभाषित किया गया है और न ही नियमों में। इसलिए, यह स्पष्ट है कि इससे पहले कि खंड 17 (2) (ii) को लागू किया जा सकता है या सेवा में सी को दबाया जा सकता है और नियम 3 के अनुसार रियायत की गणना की जाती है, शक्ति का प्रयोग करने वाले प्राधिकरण को एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि यह रियायत है। [ 320 - ए-एफ]**

*ऑफिसर्स संघ , भिल्लई स्टील प्लांट बनाम भारत संघ और अन्य।* , **(1983 ) 1 139 आई. टी. आर. 937;** *भारतीय बैंक अधिकारी संघ और अन्य बनाम भारतीय बैंक और अन्य,* **(1994) 209 आई. टी. आर. 72**; *आयकर अधिकारी बनाम अखिल भारतीय विजया बैंक अधिकारी संघ*, **(1997) 225 आई. टी. आर. 37**; *स्टील कार्यकारी संघ बनाम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड,* **(2000) 241 आई टी आर 20**; *पी. वी. राजगोपाल बनाम भारतीय संघ*, **(1998) 233 आई. टी. आर. 678**; *बी. एच. ई. एल. कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ,* **(2003) 261 आई. टी. आर. 15 (कांत)**; *बी. एच. ई. एल. कार्यकारी/अधिकारी संघ और अन्य बनाम ई डी आयकर आयुक्त और अन्य,***(2004) 264 आई. टी. आर. 390**; *अखिल भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंदौर अधिकारी को-ऑर्डिनेशन कमेटी और अन्य बनाम. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अन्य ,* **(2004) 186 सी. टी. आर. 649 (एम. पी.);** *इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम ठाणे नगर निगम,* **[1992] पूरक 1 एस. सी. सी. 480** और *वी. पेचिमेथु बनाम गौरमल*, **[2001] 7 एस. सी. सी. 617**, **का उल्लेख किया गया है।**

*ओवेन बनाम पुक*, **(1969) 74 आई. टी. आर. 147(एच. एल.);** *रैंडेल बनाम वेंट*, **[1964) 2 सभी ई. आर. 464 (एच. एल.), संदर्भित।**

*बोवियर लॉ डिक्शनरी; ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी; वेबस्टर्स न्यू अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश; संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश; पी. आर. द्वारा "उन्नत कानून शब्दकोश"। अय्यर* **(2005) खंड। 1 पी। 944 , संदर्भित किया गया।**

**3.1(ए) "क्षेत्राधिकार तथ्य" एक तथ्य है जो एक न्यायालय के समक्ष मौजूद होना चाहिए। न्यायाधिकरण या प्राधिकरण किसी विशेष मामले पर अधिकार क्षेत्र ग्रहण करता है। इस प्रकार अधिकार क्षेत्र संबंधी तथ्य का *अस्तित्व* सीमित अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती है। यदि क्षेत्राधिकार तथ्य मौजूद है, तो प्राधिकरण मामले के साथ आगे बढ़ सकता है और एक उपयुक्त सहायता ले सकता है। कानून के अनुसार निर्णय एक बार जब प्राधिकरण के पास 'क्षेत्राधिकार तथ्य' के अस्तित्व पर मामले में अधिकार क्षेत्र हो जाता है, तो वह 'मुद्दे में तथ्य' या 'न्यायिक तथ्य' तय कर सकता है। यदि क्षेत्राधिकार तथ्य मौजूद नहीं है, तो अदालत, प्राधिकरण या अधिकारी कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि कोई न्यायालय या प्राधिकरण गलत तरीके से अस्तित्व धारण करता है इस तरह के तथ्य के लिए, आदेश पर *सरशियोरेराई* के एक रिट द्वारा सवाल उठाया जा सकता है। अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि गलती से इस तरह के अधिकार क्षेत्र का अस्तित्व मानते हुए वास्तव में, कोई भी प्राधिकारी स्वयं को ऐसा अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकता है जो अन्यथा उसके पास नहीं है। इसके अलावा 'मुद्दे में तथ्य' या 'न्यायनिर्णायक' पर गलत निर्णय तथ्य अधिकार क्षेत्र के बिना प्राधिकरण का निर्णय नहीं लेगा या अधिकार क्षेत्र के अस्तित्व के रूप में आवश्यक या मौलिक तथ्य प्रदान किए गए उपस्थित है। [320 - एफ-एच; 323-एफ]**

*राजा आनंद ब्रह्मा शाह बनाम यू. पी. राज्य और अन्य* , **ए आई आर (1967) एससी 1081**: [1967] 1 एससीआर 362; *एम. पी. राज्य और बनाम वी. डी. के. जादव*, **ए आई आर (1968) एससी 1186: [ 1968 ] 2 एस. सी. आर. 823 और** *रजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी, रामपुर*, **[1973। 1 एस. सी. सी. 633: ए. आई. आर. (1973) एस. सी. 1362, संदर्भित।**

*व्हाइट एंड कॉलिन्स बनाम स्वास्थ्य मंत्री* **(1939) 2 केबी 838: 108 एलजे केआर 768 , को संदर्भित।**

*हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानून*, **को संदर्भित**।

**3.2. खंड 17 की उप-खंड (2) के खंड (ii) के तहत "रियायत" अधिनियम का एक 'क्षेत्राधिकार तथ्य' है। यह केवल तभी होता है जब किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को प्रदान किए गए किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में 'रियायत' होती है कि इस तरह की रियायत की गणना कैसे की जा सकती है। राशि निर्धारित करने की विधि 'तथ्य जारी' या 'न्यायिक तथ्य' है। यदि निर्धारिती तर्क देता है कि कोई 'रियायत' नहीं है, तो प्राधिकरण को उक्त प्रश्न पर निर्णय लेना होगा और एक निष्कर्ष दर्ज करना होगा कि क्या 'रियायत' है और मामला अधिनियम की खंड 17 (2) (ii) के अंतर्गत आता है। इसके बाद ही प्राधिकरण नियमों के तहत निर्धारिती के दायित्व की गणना करने के लिए आगे बढ़ सकता है। इसलिए, इस कानूनी स्थिति के बावजूद कि नियम 3 अधिकार केभीतर है, वैध है और अधिनियम की खंड 17 (2) (ii) के तहत मूल अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, यह अभी भी निर्धारिती जी के लिए खुला है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किए गए आवास के मामले में कोई 'रियायत' नहीं है और इसलिए मामला अधिनियम की खंड 17 (2) (ii) की शरारत के दायरे में नहीं आता है।[323 - जी-एच; 324-ए-बी]**

**3.3 खंड 17 (2) (ii) में कोई 'डीमिंग क्लॉज' नहीं है कि एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि कोई कर्मचारी अपने किराए के 10 प्रतिशत से कम का किराया दे रहा है।चार लाख की आबादी वाले शहरों में एच वेतन या अन्य शहरों में 7.5 प्रतिशत, इसे अधिनियम के अर्थ के भीतर एक 'रियायत' माना जाना चाहिए और ऐसे कर्मचारी को किराए के भुगतान में 'शर्त' के रूप में 'रियायत' प्राप्त करने वाला माना जाना चाहिए। एक नियोक्ता कई कारणों से अपने कर्मचारियों को आवासीय आवास प्रदान कर सकता है। यह भी संभव है कि कर्मचारियों के आवास/कॉलोनियों/आवास उपलब्ध कराने के लिए, राज्य सरकारें या केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कंपनियों/निगमों को नियोक्ता द्वारा वसूल किए जाने वाले किराए की राशि, यदि कोई हो, सहित उचित शर्तों को लागू करते हुए रियायती दर पर भूमि प्रदान कर सकती है। [ 324 - सी-ई]**

**3.4. नियम 3 केवल उन मामलों में लागू होगा जहां 'रियायत' दी गई है। आवास के संबंध में किराया सी के मामले में एक कर्मचारी के पक्ष में एक नियोक्ता द्वारा दिखाया गया**

**है। इस प्रकार, जबकि 'प्रभार का प्रावधान' संसद के अधिनियम (धारा 17 (2) (ii)) में पाया जाता है, 'मशीनरी खंड' अधीनस्थ विधान (नियम 3) में है। उत्तरार्द्ध केवल पूर्व के तहत देयता बनाए जाने के बाद ही लागू होगा। जब तक अधिनियम की खंड 17 (2) (ii) के तहत देयता उत्पन्न नहीं होती है, तब तक नियम 3 का कोई अनुप्रयोग नहीं है और रियायती लाभों की गणना के लिए मूल्यांकन की विधि का सहारा नहीं लिया जा सकता है।** [326 - बी-सी].

*सी. आई. टी., बॉम्बे बनाम ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडिल ईस्ट,* [2001] 8 एस. सी. सी. 36, संदर्भित को।

*अलेक्जेंडर टेनेंट बनाम रॉबर्ट स्मिथ*, **(1892) एसी 150 (एचएल)**; *टायरर बनाम स्मार्ट* **[1978] 1 ऑल ई. आर. 1089: (1978) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 415**; *होचस्ट्रैसर बनाम मेयस,* **(1960) ए. सी. 376 (एच. एल.), संदर्भित।**

**4.1. संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और कानूनों को समान सुरक्षा प्रदान करता है। यह भी सच है कि यह राज्य को प्रतिबंधित करता है व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को समान व्यवहार से वंचित करना बशर्ते वे समान हों और समान रूप से स्थित हों। लेकिन, यह समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुच्छेद 14 किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को समान रूप से स्थित अन्य लोगों से अलग होने से रोकने या प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। यदि दो व्यक्ति या दो वर्ग समान रूप से स्थित या परिस्थिति में नहीं हैं, तो उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ भिन्न व्यवहार को प्रतिबंधित करता है, लेकिन समान रूप से स्थित व्यक्तियों के वर्गीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है, बशर्ते कि ऐसा वर्गीकरण बोधगम्य अंतर पर आधारित हो और अन्यथा कानूनी, वैध और अनुमेय हो। [ 327 - बी-डी]**

**4.2. केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों यानी कंपनियों, निगमों और अन्य के कर्मचारियों के बीच नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा अंतर करने की मांग की गई। सर्वोच्च न्यायालय की अभिलेख [2006] एस. यू. पी. एस. सी. आर. एक उपक्रम बोधगम्य भिन्नता के आधार पर उचित वर्गीकरण है। जिस उद्देश्य**

**को प्राप्त करने की मांग की गई है, उसके साथ इसका तर्कसंगत संबंध भी है। नियम 3 निगमों, कंपनियों और अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को ध्यान में रखता है और सभी अनुलाभों के मूल्य की गणना करने की विधि निर्धारित करता है। इस तरह के प्रावधान** *अधिकारातीत*, **आपत्तिजनक या संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ नहीं माना जा सकता है।बी.[ 327 - जी-एच; 328-ए**

*भूतपूर्व सैनिक संघों और अन्य का परिसंघ बनाम भारत संघ और अन्य।* , **एस. सी. द्वारा 22 अगस्त, (2006) को निर्णय लिया गया।**

*एस. एल. अग्रवाल बनाम महाप्रबंधक, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड,* **[1970] 1 एससीसी सी.177 : [ 1970 ] 3 एससीआर 363;** *अजीत कुमार नाग बनाम महाप्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,* **[2005] 7 एस. सी. सी. 764;** ***बी. एच. ई. एल****. कर्मचारी संघ बनाम भारतीय संघ*, **(2003) 261 आई. टी. आर. 15 (कर) और** *आदित्य सीमेंट स्टाफ क्लब बनाम भारत संघ,* **(2004) (266) आई. टी. आर. 70, संदर्भित।**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार 2003; दीवानी याचिका सं 3270/2003

डब्ल्यू. पी. (टी) संख्या 2835/2002 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय/आदेश दिनांक 14.6.2002 के साथ

टी सी (सी) संख्या 101 और 102/2006

जगदीप धनखड़, एम. एन. कृष्णमणि, हरीश एन. साल्वे, एम. एल. वर्मा, बरुण के.सिन्हा, प्रतिभा सिन्हा, बी. के. सतीजा, सत्य मित एम. के. दुआ, यश पाल ढींगरा, अनिल मित्तल और कैलाश चंद अपीलार्थियों के लिए ।

मोहन परासरन, ए. एस. जी., नवीन प्रकाश, गौरव ढींगरा, चिदानंद डी. एल., सुलक्षणा जयराम, सेंथिल वेलन, बी. वी. बलराम दास, कीर्ति मिश्रा और रुस्तम बी. हाथीखानवाला प्रतिवादी (भारत संघ) के लिए

`रोहित सिंह, डी. के. सिन्हा, भारत संगल, एन. पी. मिधा, आर. के. कुमार, एस.चटर्जी और एल. रोशमनी एम. पी. एस. ई. बी. के लिए

एम. एल. वर्मा और पुनीत दत्त त्यागी टिस्को के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था द्वारा

**सी. के. ठाकर**, जे. सिविल अपील के साथ-साथ हस्तांतरित मामलों में, अपीलकर्ताओं ने आयकर नियम, 1962 के नियम 3, की वैधता को चुनौती दी है, जैसा कि आयकर (बाईसवां) संशोधन नियम, 2001,(इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) जिसने की गणना की विधि में संशोधन किया आयकर अधिनियम, 1961 की खंड 17 (2) के तहत अनुलाभों का मूल्यांकन (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है)। अपीलार्थियों के अनुसार,संशोधित नियम 3 मूल अधिनियम के साथ असंगत है और संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार *अधिकारातीत* है।

वर्तमान कार्यवाही में उठाए गए विवाद को समझने के लिए, दीवानी याचिका सं 2003 का 3270 कहा जा सकताहै;

अपीलार्थियों को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (संक्षेप में टिस्को) द्वारा अधिकारियों/कार्यपालकों के रूप में नियुक्त किया गया था। अपीलार्थियों के अनुसार, आम तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अपने कर्मचारियों को आवास की सुविधा प्रदान करते हैं या आवास के बदले घर का किराया भत्ता देते हैं। आमतौर पर, घर का किराया भत्ता दिया जाता है जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपने कर्मचारियों को आवास प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थितियाँ तब उत्पन्न होती हैं जब अधिकारियों/कार्यपालकों को उन शहरों या उद्यमों के महानगर कार्यालयों में तैनात किया जाता है जहां कंपनी का आवास या तो उपलब्ध नहीं है या सीमित सीमा तक उपलब्ध नहीं है। अपने कर्मचारियों के समायोजित करने के उद्देश्य से। टिस्को ने जमशेदपुर की बस्ती और उसके संयंत्रों के आसपास कई आवासीय बंगले/फ्लैट/क्वार्टर/आवास का निर्माण किया है। इन्हें इसके कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों सहित अन्य एजेंसियों को भी आवंटित किया गया था, जिन्हें या तो जमशेदपुर में स्थानांतरित या तैनात किया गया था। टिस्को ऐसे प्रत्येक के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क तय करता था। बंगलों/फ्लैटों/क्वार्टरों की पूंजी लागत/व्यय के 5 प्रतिशत की दर से आवास तय हुआ।

25 सितंबर, 2001 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अधिसूचना, सं. एस. ओ. 940 (ई) खंड 17 की उप-खंड (2) और खंड एफ की उप-खंड (2सी) के साथ पठित खंड 295 के तहत शक्ति के प्रयोग में। 192 उस अधिनियम का जिसके द्वारा नियम 3 में संशोधन किया गया था। प्रतिस्थापित नियम ने नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान किए गए किराये के आवास के मामले में अनुलाभों के मूल्यांकन की गणना करने की विधि को संशोधित किया। यह कहा गया था कि नियम 3 में संशोधन के अनुसार,प्रतिवादी सं। 4 ( टिस्को) ने 25 अक्टूबर, 2001 को एक पत्र जारी किया जिसमें अपने सभी जी कर्मचारियों को शर्तों के मूल्यांकन के संबंध में संशोधित नियम 3 के बारे में सूचित किया गया था, जिसे कर लगाने के उद्देश्य से कर्मचारियों के वेतन में जोड़ा जाना था।

उपरोक्त कार्रवाई से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने निम्नलिखित राहत के लिए रांची में झारखंड उच्च न्यायालय में 2002 की रिट याचिका संख्या 2835 दायर की।;

(i) एक उपयुक्त रिट (ओं)/आदेश (ओं)/निर्देश (ओं) जारी करने के लिए अधिसूचना सं. को रद्द करने वाली *सरशियोरेराई* प्रकृति। एस. ओ. 940 (ई) दिनांक 25.09.2001 जिसके तहत और जिसके तहत भारत सरकार द्वारा आयकर नियमों के नियम 3 में संशोधन किया गया है। वित्त मंत्रालय। राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) और इसे अधिकार *अधिकारातीत* रखने और घोषित करने का अधिकार आयकर विभाग के पास है।

(ii) एक और उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए, जिसमें प्रतिवादी, विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या को परमादेश करने वाली अनिवार्य रिट भी शामिल है। 3 और 4, रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान उपरोक्त संशोधित नियम के प्रावधानों को लागू नहीं करने के लिए,सी. और/या

(iii) कोई अन्य आदेश (आदेश)/निर्देश (निर्देश) पारित करें जैसा कि आपका प्रभु मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित मान सकता है।

उच्च न्यायालय के समक्ष कर्मचारियों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि 2001 में संशोधित नियम 3 राजस्व को मनमाने और निरंकुश शक्तियां प्रदान करता है और यह अधिनियम के अधिकार क्षेत्र *अधिकारातीत* है। यह भी आग्रह किया गया कि

गणना-विधि न तो बोधगम्य अंतर पर आधारित थी और न ही प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ इसका कोई संबंध था और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार *अधिकारातीत* है।

राजस्व द्वारा एक जवाबी शपथ पत्र दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में रेखांकित किया था कि "अनुलाभ, लाभ या सुविधाओं का मूल्य नियोक्ता को उनकी लागत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, सिवाय घर और कारों के संबंध में जहां सादगी के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाए जाएंगे।" यह कहा गया था कि नियम 3 को अपनाने और लागू करने में, जैसा कि विवादित संशोधन से पहले मौजूद था, कर्मचारियों के तीन वर्ग होने के कारण, राजस्व को विभिन्न मामलों के संबंध में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था जिसमें संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का निर्धारण भी शामिल है जो बहुत बोझिल पाया गया था। इसके अलावा, यह मेट्रो शहरों में उच्च किराए को ध्यान में नहीं रखता था। जवाब-शपथ पत्र में यह कहा गया है कि उचित किराए का अनुमान विभिन्न स्तरों पर मुकदमे का विषय रहा है, मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण कि किराए के संबंध में कानून राज्य जी विषय होने के कारण अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग थे। उचित किराए का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि सभी नगरपालिका क्षेत्रों में मानक किराया समान नहीं था। तदनुसार, आवश्यक मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया को सरल और तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया और तदनुसार, विवादित नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को केवल दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

राजस्व ने काउंटर में सरकारी कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के बीच अंतर के लिए तर्क भी समझाया था। यह कहा गया है कि संबंधित अनुलाभों के मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों को विवादित संशोधित नियम के तहत दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् (i) सरकारी (केंद्र और राज्य) कर्मचारी और (ii) अन्य अपने पारिश्रमिक और अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के अन्य लाभों के साथ निरंतरता और समानता बनाए रखने के लिए, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार देय किराए के आधार पर

आवास से संबंधित अनुलाभों के मूल्यांकन की पिछली प्रणाली को बरकरार रखा गया है। अन्य के लिए, यानी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित कर्मचारियों के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आवास से संबंधित अनुलाभों का मूल्यांकन 10प्रतिशत या वेतन का 7.5 प्रतिशत होना चाहिए। प्रतिवादीओं के दावे के अनुसार, यह निर्णय आय-कर कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।

यह देखते हुए कि चार लाख से कम आबादी वाले शहरों और चार लाख से अधिक आबादी वाले अन्य शहरों के बीच वर्गीकरण उचित और तर्कसंगत रूप से, उच्च न्यायालय ने नियम 3 की वैधता को बरकरार रखा। अदालत के अनुसार "प्रक्रिया को तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए, बोर्ड ने विवादित अधिसूचना लाई" जिसे आयोजित नहीं किया जा सका। किसी भी मापदंड या मापदंड से अनुचित। उक्त निर्णय को *टाटा श्रमिक संघ और अन्य बनाम भारत संघ* (2002) 256 आईटीआर 725 के रूप में बताया गया है।

इसी तरह का सवाल कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष कोयले के मामले में उठाया गया था *भारतीय माइन्स अधिकारी संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* , ( 2004 ) 266 आईटीआर 429. 2001 में संशोधन से पहले और संशोधन के बाद नियम 3 की भाषा पर ध्यान देंते हुए, एक एकल न्यायाधीश ने कहा कि 2001 के बाद, 'उचित किराये के मूल्य' के निर्धारण के लिए कोई एफ गुंजाइश नहीं थी। सामान्य किराए के आधार पर या इलाके में उपलब्ध बाजार किराए के आधार पर या नगरपालिका मूल्यांकन के आधार पर उचित किराये के मूल्य की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। यह भी माना गया कि नियम ने किराए के मामले में रियायत के मूल्य का पता लगाने के लिए विधि और आधार तैयार किया जिसे घोषित नहीं किया जा सकता था मनमाना या *अधिकारातीत* है। अदालत का यह भी विचार था कि सरकारी कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के बीच का अंतर संविधान का अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी नहीं था।

वर्तमान मामलों में झारखंड और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों के फैसलों की शुद्धता पर सवाल उठाए गए हैं।

हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश साल्वे ने कई तर्क उठाए। उन्होंने आग्रह किया कि नियमों के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की खंड 17 (2) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्व शर्त यह है कि यह अधिनियम के अर्थ के भीतर एक "शर्त" होनी चाहिए। खंड 17 की उप-बी खंड (2) के खंड (ii) को आकर्षित किया जा सकता है बशर्ते कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को प्रदान किए गए किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में "रियायत" हो। यदि कोई "रियायत" नहीं है, तो पूर्ववर्ती शर्त या *शर्त अनुपस्थिति* है और कोई "शर्त" भी नहीं है। चूंकि तत्काल मामले में कोई रियायत नहीं है, इसलिए अधिनियम की खंड 17 (2) (ii) लागू नहीं होगी और न ही नियमों का नियम 3 आकर्षित होता है और न ही कोई देयता उत्पन्न होती है। यह था। वैकल्पिक रूप से आग्रह किया गया कि 2001 में अपने संशोधन से पहले पुराने नियम 3 ने यह प्रावधान करते हुए एक 'विंडो' उपलब्ध कराई कि जिन मामलों में निर्धारिती ने दावा किया था और निर्धारण अधिकारी संतुष्ट थे कि कोई 'रियायत' नहीं थी, वहां निर्धारिती कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। 2001 में संशोधित नियम ने निर्धारिती के यह दावा करने के अधिकार को छीन लिया है कि खंड 17 (2) (ii) द्वारा परिकल्पित के रूप में कोई रियायत नहीं थी और इसलिए नियम 3 का कोई अनुप्रयोग नहीं था। इसी तरह, इसने निर्धारण अधिकारी की यह अभिनिर्धारित करने की शक्ति छीन ली कि कोई रियायत नहीं थी। भले ही वह 'रियायत' की अनुपस्थिति में के बारे में संतुष्ट हो। अधिनियम के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए रियायत "क्षेत्राधिकार तथ्य" है और इसके अभाव में, प्राधिकरण कर देयता को लागू नहीं कर सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि नियम 3 में, न्यायालय भाषा की अवधारणा को लागू कर सकता है। 'नीचे पढ़ने' की प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक न्याय का पालन। ऐसी प्रक्रिया से नियम 3 को मनमानेपन और अनुचितता से बचाया जा सकता है। यदि ऐसी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप

से या निहित रूप से प्रतिबंधित किया जाता है, तो नियम मनमाना हो जाता है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के अधिकार *अधिकारातीत* हो जाता है। श्री साल्वे के अनुसार, मूल अधिनियम निर्धारिती एफ पर अपने कर्मचारी के वेतन से स्रोत पर कर की कटौती करने का दायित्व लगाता है बशर्ते कि नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को रियायती दर पर आवास दिया हो। नियम 3 केवल दायित्व की गणना का तरीका, विधि या तरीका प्रदान करता है और इस प्रकार यह एक "तंत्र" प्रावधान है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, देयता को कानून के तहत एक सक्षम अधिनियममंडल द्वारा तय किया जाना चाहिए, यानी अधिनियम की खंड 17 (2) (ii) के तहत और इस तरह के दायित्व को तय करने के बाद ही, प्रश्न इसकी गणना की जाएगी जो नियमों के नियम 3 के तहत मशीनरी प्रावधान द्वारा की जा सकती है। नियम 3, जो एक बाल विधान है, प्रत्यायोजित विधान या अधीनस्थ विधान नियोक्ता पर कर की कटौती करने या कर्मचारी पर कर का भुगतान करने का दायित्व यह मानते हुए नहीं लगा सकता है कि रियायती किराया अधिनियम की खंड 17 (2) (ii) के अर्थ के भीतर 'आवश्यक' था। वह विधानमंडल का अनन्य क्षेत्र है। चूंकि कोई 'रियायत' नहीं थी, इसलिए नियम 3 का कोई अनुप्रयोग नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि राजस्व की ओर से यह तर्क कि किराए की राशि की गणना करने और व्यक्तिगत मामलोंसे निपटने में राजस्व की "व्यावहारिक कठिनाइयों"के कारण सपाट दरें तय करके इस तरह का मार्ग अपनाया गया था, न केवल अप्रासंगिक और महत्वहीन है, बल्कि अवैध है। गैरकानूनी और कानून की शक्ति या अधिकार के बिना। वकील ने निष्पक्ष रूप से कहा कि बी एक मोटे और तैयार परीक्षण के रूप में, जनसंख्या के आधार पर किराया तय करने के लिए नियम 3 में निर्धारित प्रक्रिया आपत्तिजनक नहीं हो सकती है, लेकिन यह केवल तभी साबित होता है जब नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किए गए किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में रियायत है कि ऐसी विधि लागू की जा सकती है। हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में भी होना चाहिए निर्धारिती को यह तर्क देने की अनुमति या अनुमति देने वाला प्रावधान हो कि कोई रियायत नहीं है। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री धनखड़, श्री साल्वे के तर्कों को अपनाया। हालाँकि, उन्होंने यह भी तर्क

दिया कि एक ओर सरकार के कर्मचारियों और दूसरी ओर कंपनियों, निगमों या अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों के बीच किया जाने वाला अंतर कृत्रिम औरतर्कहीन है, जो न तो बोधगम्य अंतर पर आधारित है और न ही इसे प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ कोई संबंध है। इस प्रकार दोनों वर्गों के बीच 'शर्त' पर विचार करते समय भुगतान का अंतर मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार क्षेत्र अधिकारातीत होगा। श्री परासरन, राजस्व की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने वर्तमान कार्यवाही में विवादित निर्णयों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि 2001 से पहले के नियम "आवास के उचित किराये के मूल्य" पर आधारित थे। उक्त अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, यह निर्धारिती को एक अवसर प्रदान करता है, यदि वह निर्धारण अधिकारी को संतुष्ट करने का दावा करता है कि राशि नियम 3 के आधार पर आई है, जैसा कि तब था, आवास के ऐसे 'उचित किराये के मूल्य' से अधिक नहीं थी और इसलिए अधिनियम की खंड 17 (2) (ii) के अर्थ के भीतर 'शर्त' नहीं कहा जा सकता था। राजस्व द्वारा महसूस की गई व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए आवास के उचित किराये के मूल्य की अवधारणा को मंजूरी दी गई है। 2001 के संशोधित नियम के तहत, "उचित किराया", "बाजार किराया", "मानक किराया", "उचित किराया" आदि की कोई प्रासंगिकता नहीं है। जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए और आम तौर पर चार लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और अन्य शहरों में किराया लेने के नियम में संशोधन किया गया है। यह एक प्रासंगिक और व्यापक विचार है जिसे न तो मनमाना कहा जा सकता है और न ही अनुचित, और न ही संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला। श्री परासरन के अनुसार, अंततः यह प्राधिकरण द्वारा लिया गया एक नीतिगत निर्णय था कि आवश्यकता की गणना कैसे की जानी चाहिए। 2001 से पहले सरकार ने एक नीति को स्वीकार

किया था। उक्त नीतिबाद में इसे बदल दिया गया और अब नई नीति तैयार की गई है। इस तरह के नीतिगत मामलों में, आम तौर पर, एक अदालत तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि नीति पूरी तरह से मनमाना या अनुचित न हो। यह भी प्रस्तुत किया गया कि संशोधित नियम को नियोक्ताओं और कर निर्धारकों द्वारा चुनौती दी गई थी और कई उच्च न्यायालयों ने इसकी वैधता को बरकरार रखा था। श्री परासरन के अनुसार, सभी प्रासंगिक

तथ्यों पर विचार करते हुए, राजस्व द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि चार लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वेतन के 10 प्रतिशत से कम और अन्य शहरों में वेतन के 7.5 प्रतिशत से कम पर आवास प्रदान करना नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को प्रदानकिए गए ऐसे आवास के संबंध में किराए के मामले में "रियायत" माना जाएगा। इस तरह के निर्णय के आलोक में, नियम 3 को मूल अधिनियम या संविधान के अधिकार क्षेत्र अधिकारातीत नहीं माना जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि यहन्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि किराए के मामले में "रियायत" अधिनियम की खंड 17 (2) (ii) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है और उसके बाद ही नियम 3 का तंत्र प्रावधान लागू होगा, न्यायालय 'निर्धारिती को निर्धारण डी अधिकारी को संतुष्ट करने का अवसर प्रदान करके कि कोई रियायत नहीं थी' इसे अधिकार के भीतर और संवैधानिक रूप से रखने के सिद्धांत का आह्वान कर सकता है। सरकारी कर्मचारियों और कंपनियों, निगमों और अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों के बीच भेदभाव के बारे में उन्होंने कहा कि यह एक वैध वर्गीकरण है और यह समझदार अंतर पर आधारित है। यह कर्मचारियों के दो समूहों की स्थिति पर विचार करके एक उद्देश्य को प्राप्त करने का भी प्रयास करता है। इस तरह के प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए रद्द नहीं किया जा सकता है।

इससे पहले कि हम पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, यह उचित हो सकता है कि हम अधिनियम, नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख और मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्णय करें। अधिनियम की खंड 17 वेतन ',' शर्त 'और' वेतन के बदले में लाभ 'को परिभाषित करती है। उक्त खंड का प्रासंगिक खंड इस प्रकार है

17. खंड 15 और 16 और इस खंड के प्रयोजनों के लिए।

(1) ..... .....

(2) अनुलाभ में शामिल हैं

(i) आवंटन प्राप्तकर्ता के नियोक्ता द्वारा दिए गए किसी आवास के किराए मे कोई रियायत का मूल्य।

(ii) नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को प्रदान किए गए किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में किसी भी रियायत का मूल्य ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'शर्त' शब्द की परिभाषा में विभिन्न शामिल हैं।

उसमें उल्लिखित वस्तुएँ। यह भी स्पष्ट है कि परिभाषा समावेशी प्रकृति की है और संपूर्ण नहीं है।

*बोवियर के लॉ डिक्शनरी* के अनुसार, अभिव्यक्ति 'अनुलाभ' में है। सबसे सीमित ज्ञान का अर्थ है "नियमित वेतन या शुल्क से परे किसी स्थान या कार्यालय द्वारा प्राप्त कुछ"।

*ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी* 'अनुलाभ' को 'किसी भी आकस्मिक' के रूप में परिभाषित करती है। वेतन या मेहनताना के अलावा किसी कार्यालय या पद से जुड़ा परिलब्धि, शुल्क या लाभ।

*वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी* के अनुसार, 'अनुलाभ' नियमित वेतन या मजदूरी के अलावा संयोग से

रोजगार से प्राप्त लाभ या लाभ है, विशेष रूप से अपेक्षित या वादा की गई एक तरह का।

'इस प्रकार 'शर्त' नियमित वेतन या मजदूरी केअलावा किसी रोजगार के लिए एक विशेषाधिकार, लाभ या मुनाफा है।

जैसा कि *ओवेन बनाम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स* द्वारा देखा गया है। पूक, (1969) 74 आई. टी. आर. 147 (एच.एल.), 'अनुलाभ' का एक ज्ञात सामान्य अर्थ है, अर्थात् एक व्यक्तिगत लाभ। यह शब्द केवल आवश्यक संवितरण की प्रतिपूर्ति पर लागू नहीं होगा। *रेंडेल बनाम वेंट*, [1964] 2 सभी ई. आर. 464 (एच. एल.), सदन ने माना कि कोई भी लाभ या लाभ, जिसका धन मूल्य है, जो कंपनी के तहत कार्यालय का धारक अपनी ओर से कंपनी के खर्च से प्राप्त करता है।'अनुलाभ' शब्द के अंतर्गत आएगा।

भारतीय न्यायालयों ने यह भी माना है कि 'शर्त' एक लाभ या लाभ है। किसी पद के धारक द्वारा अपने वेतन से अधिक प्राप्त किया जाता है। एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त लाभ वेतन से अधिक या एफ में रोजगार के लिए आकस्मिक है।

अधिनियम की खंड 295 बोर्ड को सक्षम बनाती है [जैसा कि अधिनियम के खंड (12) में परिभाषित किया गया है। खंड 2 अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए

नियम बनाने के लिए केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम,1963 के तहत गठित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के रूप में।

प्रासंगिक भाग इस प्रकार है;

" 295. नियम बनाने की शक्ति। (1) बोर्ड केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन हो सकता है, भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पूरा करने के लिए पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए नियम बना सकता है इस अधिनियम के उद्देश्य।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले का प्रावधान कर सकते हैं.

ए..... बी

(सी) इस अधिनियम के तहत कर के लिए प्रभार्य किसी भी शर्त के मूल्य का निर्धारण इस तरह से और ऐसे आधार पर किया जाए जो बोर्ड को उचित और तर्कसंगत लगे।“

..... ..... .....

अधिनियम की खंड 192 की उप-खंड (2सी) यह अधिनियमित करती है कि एक व्यक्ति "वेतन" शीर्ष के तहत प्रभार्य किसी भी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उस व्यक्ति को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसे ऐसा भुगतान किया जाता है जिसमें उसे प्रदान किए गए वेतन के बदले में अनुलाभों या लाभों का सही और पूरा विवरण और उसके मूल्य को ऐसे रूप और तरीके से दिया जाता है जो निर्धारित किया जाए।

अधिनियम की खंड 295 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, बोर्ड ने आयकर नियम, 1962 के रूप में जाने जाने वाले नियम बनाए। नियम 3 अनुलाभ के मूल्यांकन की गणना करने की विधि निर्धारित करता है। 2001 में संशोधन से पहले, उक्त नियम का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पढ़ा गया था -

अनुलाभों का मूल्यांकन।

3. के अधीन प्रभार्य आय की गणना करने के उद्देश्य से शीर्ष "वेतन" अनुलाभों का मूल्य (निर्धारिती को मौद्रिक भुगतान के रूप में प्रदान नहीं किया गया) नीचे उल्लिखित होगा -

निम्नलिखित खंडों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, अर्थात्:

( क) किराया-मुक्त आवासीय आवास का मूल्य यहाँ दिए गए आधार पर निर्धारित किया जाएगा, अर्थात्:

(i) जहाँ आवास प्रदान किया जाता है -

(क) सरकार द्वारा संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में किसी पद या पद पर आसीन व्यक्ति को;

(ख) सरकार के नियंत्रण में किसी निकाय या उपक्रम द्वारा सरकार के किसी ऐसे अधिकारी को, जिसकी सेवाएँ उस निकाय या उपक्रम को दी गई हों। (सरकार द्वारा इसे आवंटित किया गया था),

के बराबर राशि

(1) यदि आवास अनुपलब्ध है तो वह किराया जो बी सरकार द्वारा अपने अधिकारियों को आवासों के आवंटन के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति या अधिकारी द्वारा देय के रूप में निर्धारित किया गया है या किया गया होगा;

(2) यदि आवास प्रस्तुत किया जाता है, तो उपखंड (i) (1) के साथ-साथ फर्नीचर की मूल लागत (10 प्रतिशत सहित) प्रति वर्ष के अनुसार गणना की गई राशि। टेलीविजन सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू सी उपकरण और वातानुकूलन संयंत्र या उपकरण) या यदि ऐसा फर्नीचर किसी तीसरे पक्ष से किराए पर लिया जाता है, तो वास्तविक किराया शुल्क देय है;]

बशर्ते कि

( 1 ) जहां आवास का उचित किराया मूल्य निर्धारिती के वेतन के 20 प्रतिशत से अधिक है, वहां आवश्यकता का मूल्य उस राशि के बराबर राशि से बढ़े हुए वेतन का 10 प्रतिशत माना जाएगा, जिसके द्वारा उचित किराया मूल्य वेतन के 20 प्रतिशत से अधिक हो जाता है। आवास की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उस राशि का निर्धारण करें जिसके द्वारा वेतन का 10 प्रतिशत बढ़ाया जाना है, उस राशि के प्रतिशत (100 प्रतिशत से अधिक नहीं) के रूप में जिसके द्वारा उचित किराया मूल्य वेतन के 20 प्रतिशत से अधिक है।

( 2 ) जहाँ निर्धारिती दावा करता है, और निर्धारण अधिकारी संतुष्ट है कि ऊपर दिए गए आधार पर प्राप्त राशि आवास के उचित किराये के मूल्य से अधिक है, निर्धारिती के लिए आवश्यकता का मूल्य ऐसे उचित किराये के मूल्य तक सीमित होगा;

( ख) रियायती किराए पर प्रदान किए गए आवासीयआवास का मूल्य उस राशि के रूप में निर्धारित किया जाएगा जिसके द्वारा खंड (क) के अनुसार संगणित जी मूल्य, जैसे कि आवास किराए से मुक्त प्रदान किया गया था, निर्धारिती द्वारा प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान अपने व्यवसाय की अवधि के लिए वास्तव में देय किराए से अधिक है।

आयकर (बाईसवाँ संशोधन) नियम, 2001, नियम 3 के अनुसार संशोधित किया गया था और प्रासंगिक भाग इस प्रकार है :

" 3. अनुलाभों का मूल्यांकन

'वेतन' शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना करने के उद्देश्य से, नियोक्ता द्वारा निर्धारिती (इसके बाद 'कर्मचारी' के रूप में संदर्भित) या उसके परिवार के किसी सदस्य को उसके रोजगार के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान किए गए अनुलाभों का मूल्य निम्नलिखित उप-नियम के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, अर्थात्

(1) पिछले वर्ष के दौरान नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए आवासीय आवास का मूल्य नीचे दी गई तालिका में दिए गए आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

| क्रम संख्या | परिस्थितियाँ | जहाँ आवास असज्जित है | जहाँ आवास सुसज्जित है |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (I) | जहां केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारियों को आवास प्रदान किया जाता है जो या तो संघ या ऐसे राज्य के जोड़े के संबंध मे कार्यालय या पद धारण करते है या प्रतिनियुक्ति पर ऐसी सरकार के नियंत्रण मे किसी निकाय समझ के साथ सेवा करते हैं। | केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आवास के संबंध मे ऐसी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित लाइसेन्स शुल्क , जो कर्मचारियों द्वारा वास्तव मे भुगतान किए गए किराए से कम हो जाता है । | खरीद का मूल्य कॉलम 3 के तहत निर्धारित किया गया है और (टेलीविजन सेट , रेडियो सेट , रेफ्रीजरेटर, अन्य घरेलू उपकरण , एयर कन्डिशनिंग संयंत्र या उपकरण)सहित फर्निचर की लागत का प्रति राशि 10% बढ़ाया गया है या यदि ऐसा फर्निचर किसी तीसरे पक्ष से छिपा हुआ है , तो वास्तविक शुल्क देय होगा। पिछले वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा भुगतान किए गए या देय किसी भी शुल्क से कम किया गया है। |
| (2) | जहां आवास किसी अन्य नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया हो और (ए) | (i)1991 के जनगणना के अनुसार 4 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों मे | खरीद का मूल्य कॉलम 3 के तहत निर्धारित किया गया है और |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | जहां आवास नियोक्ता के स्वामित्व मे है या (बी)जहां नियोक्ता द्वारा आवास पट्टे या किराये पर लिया गया है। | वेतन का 10%<br>(ii)पिछले वर्ष के दौरान जिस अवधि के दौरान कर्मचारी द्वारा उक्त आवास पर कब्जा किया गया था, उस अवधि के संबंध मे अन्य शहरों मे 75% वेतन, यदि कर्मचारी द्वारा वास्तव मे भुगतान किया गया कोई किराया हो,तो उसे कम कर दिया जाएगा। | (टेलीविजन सेट , रेडियो सेट , रेफ्रीजरेटर, अन्य घरेलू उपकरण , एयर कन्डिशनिंग संयंत्र या उपकरण)सहित फर्निचर की लागत का प्रति राशि 10% बढ़ाया गया है या यदि ऐसा फर्निचर किसी तीसरे पक्ष से छिपा हुआ है , तो वास्तविक शुल्क देय होगा। पिछले वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा भुगतान किए गए या देय किसी भी शुल्क से कम किया गया है। |
| (3) | जहां ऊपर क्रम संख्या एक या दो मे निर्दिष्ट कर्मचारी द्वारा किसी होटल मे आवास उपलब्ध कराया जाता है , जहां कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण पर कुल मिलाकर 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसा आवास प्रदान नहीं | लागू नहीं | पिछले वर्ष के लिए भुगतान किए गए या देय वेतन का 24% या होटल खोजने के लिए भुगतान किए गए या देय वास्तविक शुल्क , जो उस अवधि के लिए कम है , जिसके दौरान ऐसा आवास प्रदान किया गया है , किराय |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | किया जाता है। | | से घटाकर यदि कोई वास्तव मे भुगतान किया गया हो या कर्मचारी द्वारा देय हो। |

बशर्ते कि इस उप-नियम में कुछ भी निहित नहीं होगा खनन स्थल या तटवर्ती तेल अन्वेषण स्थल, या परियोजना निष्पादन स्थल में प्रदान किए गए आवास पर काम करने वाले कर्मचारी को प्रदान किए गए 'दूरस्थ क्षेत्र' में स्थित किसी भी आवास पर लागू होता है। समान प्रकृति का अपतटीय स्थल;

बशर्ते कि जहां कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के कारण, दूसरे स्थान पर आवास बनाए रखते हुए पोस्टिंग के नए स्थान पर आवास प्रदान किया जाता है, वहां आवश्यकता का मूल्य केवल एक ऐसे आवास के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा जिसका मूल्य 90 दिनों सेअधिक की अवधि के लिए उपरोक्त तालिका के संदर्भ में कम हो और उसके बाद ऐसी दोनों आवासों के लिए आवश्यकता का मूल्य तालिका के अनुसार लिया जाएगा।

..... ..... .....

नियम 3, संशोधन से पहले और 2001 के संशोधन के बाद भी विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ-साथ कुछ मामलों में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने उन निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

अपीलार्थियों के लिए श्री साल्वे ने निर्णय पर भारी निर्भरता रखी *ऑफिसर्स संघ , भिलाई स्टील प्लांट बनाम भारत संघ और अन्य,* (1983) 139 आई. टी. आर. [937] में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के मामले में ऑफिसर्स संघ , भिलाई द्वारा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी इस्पात संयंत्र और संभागीय प्रबंधक (निर्माण)। संभागीय प्रबंधक एक चौथाई के व्यवसाय में था जिसका किराया रु 100 / - प्रति माह मौलिक नियमों के नियम 45ए के तहत मानक किराए के रूप में तय किया गया था जो

अधिकारियों पर लागू किया गया था। अधिनियम की खंड 192 के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती करते हुए, प्रबंधन कर्मचारी के वेतन के 1/10वें हिस्से और उसके द्वारा भुगतान किए गए किराए के बीच के अंतर को आवश्यकता के अनुसार मान रहा था। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि केवल इसलिए कि एक अधिकारी द्वारा भुगतान किया गया किराया उसके वेतन के दसवें हिस्से से कम था, अंतर को आवश्यकता के रूप में नहीं माना जा सकता है और उस आधार पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जा सकती है। इसलिए, एक प्रार्थना की गई कि अधिकारियों को स्रोत पर आयकर की कटौती के उद्देश्यों के लिए वेतन के 10 प्रतिशत और वास्तव में भुगतान किए गए किराए के बीच के अंतर को 'आवश्यकता' के रूप में मानने से रोका जाए।

आयकर अधिकारियों ने वेतन के 10 प्रतिशत और भुगतान किए गए किराए के बीच के अंतर को 'आवश्यकता' मानने के लिए प्रबंधन को कोई परिपत्र या निर्देश जारी करने से इनकार किया, लेकिन कहा कि यह सही कानूनी स्थिति थी।

इसलिए, उच्च न्यायालय को यह तय करने के लिए कहा गया था कि क्या नियमों के नियम 3 के साथ पठित खंड 17 (2) (ii) के प्रावधान लागू होंगे और क्या राजस्व द्वारा तर्क दिए जाने के अनुसार अंतर को 'आवश्यकता' मानते हुए स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता थी। न्यायालय ने स्वीकार किया कि खंड 17 की उप-खंड (2) में 'आवश्यकता और उप-खंड (ii)' को परिभाषित किया गया है, जिसमें 'निर्धारिती को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में किसी भी रियायत का मूल्य' शामिल है, लेकिन यह 'किराए के मामले में कोई रियायत' थी जो उस खंड में शामिल थी।

न्यायालय ने कहा;

धारा 3 का उद्देश्य कर के लिए अनुलाभ प्रभार्य के मूल्य का निर्धारण है। *नियम उस स्तर पर काम करता है जब कोई निष्कर्ष निकाला जाता है कि कर्मचारी को धारा में परिभाषित किसी भी आवश्यकता की प्राप्ति हो रही है। 17 (2) . इस नियम का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है कि अधिकारी को वास्तव में कोई आवश्यकता प्राप्त हो रही है या नहीं।* नियम केवल इसके लिए लागू होता है जब प्राप्ति का

तथ्य हो तो परिलब्धि का मूल्य निर्धारित करना अन्यथा शर्त स्थापित की जाती है। नियम 3 (ए) उस मामले से संबंधित है कर्मचारी किराया-मुक्त आवासीय आवास के व्यवसाय में है। यदि यह तथ्य कि कर्मचारी किराया-मुक्त आवास के व्यवसाय में है, स्थापित हो जाता है, तो उसके मूल्य की गणना नियम 3 (ए) में दी गई विधि को लागू करके की जाएगी। इसी तरह नियम 3 (बी) तब लागू होता है जब कर्मचारी रियायती किराए पर आवासीय आवास पर कब्जा कर रहा हो. कर्मचारी वास्तव में रियायती किराए पर आवास का व्यवसाय करता है, उसके मूल्य की गणना इस नियम में प्रदान किए गए तरीके से की जाएगी। किराया-मुक्त बिना साज-सज्जा वाले आवास का मूल्य 10 प्रतिशत लेने में नियम का प्रभाव यह नहीं है कि जिस समय यह पाया जाता है कि कोई कर्मचारी किराए के रूप में अपने वेतन का 10 प्रतिशत से कम भुगतान कर रहा है, यह माना जाना चाहिए कि उसे रियायती किराए पर आवास प्रदान किया गया है।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने विचार किया कि सवाल यह था कि क्या कोई कर्मचारी रियायती दर पर आवास का व्यवसाय कर रहा था, वह डी है, क्या कर्मचारी को कोई रियायत मिली थी जिसे 'आवश्यकता' कहा जा सकता है और जवाब दिया कि यह दो कारकों पर निर्भर करेगा; (i) कर्मचारी के व्यवसाय में आवास के लिए सामान्य किराया; और

(ii) कर्मचारी द्वारा वास्तव में भुगतान किया गया किराया। यदि कर्मचारी द्वारा दिया गया किराया उसके व्यवसाय में आवास का सामान्य किराया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे किराए के मामले में कोई रियायत मिल रही है, भले ही उसके द्वारा दिया गया किराया उसके वेतन के 10 प्रतिशत से कम हो।

इसके बाद न्यायालय ने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कीं-

.....धारा 17(2) में निहित "अनुलाभ" की परिभाषा में कोई अनुमान खंड नहीं है। एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि कोई कर्मचारी अपने वेतन के 10 प्रतिशत से कम किराया दे रहा है, यह माना जाना चाहिए कि वह है किराया के मामले में रियायत प्राप्त करना और इस तरह के किसी भी खंड का अनुमान *नियम 3 से नहीं लगाया जा सकता है।*

*वास्तव में, यदि नियम 3 इस तरह से समझा जाना था, यह एस द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति से परे जाएगा। 295 ( 2 ) और अमान्य हो जाएगा।*

(जोर दिया गया)

*भारतीय बैंक अधिकारी संघ और अन्य बनाम भारतीय बैंक और अन्य*, (1994) 209 आई. टी. आर. 72, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने फिर से इसी तरह के प्रश्न पर विचार किया। वहाँ एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों को आवास प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ता जो बैंक के कर्मचारी थे, बैंक के नियम द्वारा निर्धारित मानक किराए के अनुसार किराए का भुगतान कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं के समान स्थित अन्य सभी कर्मचारी भी उसी तरीके से और उसी हद तक किराया दे रहे थे। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इन परिस्थितियों में अधिनियम की खंड 17(2) (ii) के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ताओं द्वारा किसी भी रियायत का आनंद नहीं लिया जा सकता है और नियमों के नियम 3 के तहत आवास के काल्पनिक आवश्यक मूल्य पर कोई कर कटौती योग्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि रियायत का प्रश्न प्रदान किए गए आवास की प्रकृति के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। समान रूप से स्थित अन्य कर्मचारियों द्वारा ऐसे आवास के संबंध में देय सामान्य किराया और संबंधित कर्मचारी द्वारा भुगतान किया गया वास्तविक किराया।

*अधिकारी संघ, भिलाई स्टील प्लांट* में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत को दोहराते हुए, न्यायालय ने कहा कि नियम 3 में जो कहा गया है वह अनुलाभों का मूल्यांकन और उनकी गणना का तरीका है बशर्ते कि यह एक रियायत या आवश्यकता हो। हालाँकि, नियम में किसी भी दायित्व को तय करने का प्रयास नहीं किया गया था जो अधिनियम की खंड 17 (2) द्वारा नहीं बनाया गया था।

सबसे पहले और उसके बाद ही इस तरह की शर्त के मूल्य की गणना करने का सवाल उठेगा। घोड़े के आगे गाड़ी नहीं रखी जा सकती। प्रदत्त मूल्यांकन की विधि का पालन करके, आयकर अधिकारी निर्धारित नहीं कर सकते हैंन्यायालय के अनुसार, शर्त का प्रश्न निर्धारित

किया जाना चाहिए शर्तों का अस्तित्व। यह केवल अधिनियम की खंड 17 (2) के तहत ही किया जा सकता है। *इस नियम को अधिनियम के मूल प्रावधानों के तहत प्रदान शक्तियों से परे पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।*

(जोर दिया गया)

ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले को *आयकर अधिकारी बनाम अखिल भारतीय विजया बैंक अधिकारी संघ,* (1997) 225 आईटीआर 37 मामले में खण्ड पीठ ने अंतर-अदालत अपील के माध्यम से लिया गया था और खण्ड पीठ के समक्ष अपील को खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि की।

*स्टील कार्यकारी संघ बनाम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड*, (2000) 241 आई. टी. आर. 20, फिर से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक समान प्रश्न उठा। वहाँ नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को आवास प्रदान किया गया था और उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न आया था वह यह था कि क्या यह अधिनियम और नियमों के अर्थ के भीतर आवश्यक था और क्या नियोक्ता को स्रोत पर कर की कटौती करने की आवश्यकता थी। अदालत ने *अधिकारी संघ , भिलाई स्टील प्लांट और भारतीय बैंक अधिकारी संघ* के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि यह प्रावधान केवल उन मामलों में लागू होगा जहां किराए का भुगतान रियायती शुल्क पर किया गया था। यदि किराया रियायती नहीं था, तो विभाग नियोक्ता को स्रोत पर कर काटने के लिए नहीं कह सकता था मानक किराए को रियायती किराए के रूप में मानना और ऐसी कार्रवाई को कानूनी या विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि प्रावधान को ध्यान से पढ़ते हुए, यह स्पष्ट था कि यह केवल आवश्यकता के मूल्यांकन के लिए प्रदान किया गया था यदि आवासीय आवास रियायती दर पर प्रदान किया गया था।

न्यायालय ने कहा;

इसलिए, राजस्व के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि प्रभारित किराया एक रियायती किराया है, इससे पहले कि यह कहा जा सके कि एक शर्त है और उसके बाद, ऐसी

शर्त का मूल्यांकन भुगतान किए गए वास्तविक किराए और वेतन के 10 % के बीच के अंतर के रूप में किया जाएगा। इस मामले में जो हुआ है वह यह है कि राजस्व ने घोड़े के सामने गाड़ी रखा है और मान लिया कि एक रियायत है क्योंकि किराया वेतन के 10 प्रतिशत से कम है।

( जोर दिया गया)

न्यायालय ने राजस्व की ओर से इस निवेदन पर ध्यान दिया कि वास्तव में एक रियायत थी क्योंकि आयकर अधिकारी के पास के लिए सामग्री थी जो इंगित करती है कि प्रदान किए गए आवास का उचित बाजार मूल्य वेतन के 10 प्रतिशत से बहुत अधिक था। लेकिन, न्यायालय ने तर्क को नकार दिया और कहा;

> हम उस सामग्री को किसी भी रियायत का संकेत देने के रूप में प्रतिग्रहण करना करने में असमर्थ हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में जहां नियोक्ता अपनी सुविधा के लिए उपयुक्त स्थान पर अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी संख्या में आवासीय आवास का निर्माण करता है, ऐसे कर्मचारियों का उचित बाजार किराया आवास का निर्धारण किराए के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है। शहर में उपलब्ध किसी भी अन्य प्रकार का आवास, भले ही वह पास में ही हो। एक शहर में नियमित आवासों का अपना वातावरण होता है जिसकी तुलना कर्मचारी का पता लगाने के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किराये के साथ नहीं की जा सकती क्योंकि कर्मचारी के पास उस आवास को स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं होता है। रोजगार के लिए कई अन्य कारण हैं और कर्मचारियों को उपलब्ध रखने और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियोक्ता की आवश्यकताएं हैं जो आवास के किराए के निर्धारण में जाती हैं।

न्यायालय ने *पी. वी. राजगोपाल बनाम भारत संघ*, (1998) 233 आई. टी. आर. 678 में अपने पहले के निर्णय का भी उल्लेख किया और कहा कि विभाग नियोक्ता को उस राशि के स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है जो नियोक्ता द्वारा एक शर्त के रूप में विवाद में थी।

दूसरी ओर श्री परासरन ने कहा कि कई उच्च न्यायालयों ने उक्त नियम के तहत शर्तों के निर्धारण के लिए राजस्व द्वारा अपनाई गई विधि को मंजूरी देकर नियम 3 की वैधता को बरकरार रखा। दो उच्च न्यायालयों अर्थात झारखंड उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय हमारे सामने हैं। झारखंड के उच्च न्यायालय ने, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, नियम 3 की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि संसद में वित्त मंत्री के बजट भाषण के परिणामस्वरूप संशोधन लाया गया था। इसके अलावा, यह निर्णय आयकर कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिश पर लिया गया था।

श्री परासरन ने *भारतीय कोल माइंस अधिकारी संघ* का भी उल्लेख किया, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फिर से इस पर विचार किया। अधिनियम के खंड 17 (2) (ii) के तहत किराए के मामले में "रियायत" अभिव्यक्ति दिया। वहाँ भी, कर्मचारियों की ओर से यह तर्क दिया गया था कि चूंकि किराए के मामले में कोई "रियायत" नहीं थी, इसलिए इसे अधिनियम की खंड 17 (2) (ii) के तहत शर्त नहीं कहा जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया था कि “रियायत” है या नहीं, यह पहले तय किया जाना चाहिए। उक्त उद्देश्य के लिए, यह निर्धारित करना आवश्यक था कि किराया क्या होगा और यदि नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को ऐसे किराए से कम दर पर आवास प्रदान किया जाता है, तो इसे अधिनियम की खंड 17 (2) (ii) के तहत 'रियायत' के रूप में माना जाएगा और इसकी गणना नियमों के नियम 3 के तहत की जानी होगी।

हालाँकि, न्यायालय ने संकेत दिया कि पिछले निर्णय नियम 3 से संबंधित थे जैसा कि यह तब था जिसने 2001 में संशोधन के बाद निर्धारित की गई विधि से पूरी तरह से अलग विधि निर्धारित की थी।

अदालत ने तब कहा -

> इस प्रकार, वर्तमान नियम विशेष रूप से किराया-मुक्त आवास के मूल्य का पता लगाने की विधि और आधार तैयार करने के लिए संबोधित नहीं करता है; यह स्पष्ट रूप से विधि और आधार तैयार करने के लिए भी संबोधित करता है। किराया के मामले में रियायत के मूल्य का निर्धारण करना। हालांकि, ऐसा करते हुए इसने

रियायत के मूल्य को स्पष्ट कर दिया, जो पिछले नियम में निहित था। इसे तैयार करते समय इसने दो प्रकार के कर्मचारियों को वर्गीकृत किया है। उनमें से पहला शुद्ध सरकारी कर्मचारी है और दूसरा अन्य सभी कर्मचारी हैं। इसके अलावा, इसने दो प्रकारों को वर्गीकृत किया आवास-एक सरकार द्वारा प्रदान किया गया और दूसरा अन्य सभी द्वारा प्रदान किया गया। जहाँ तक सरकारी कर्मचारियों का संबंध है, जिन्हें सरकारी आवास प्रदान किया गया है, नियम कहता है कि किराए का मूल्य-अनुलाभ के रूप में मुफ्त के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित लाइसेंस शुल्क होगा, नियमों और रियायत के मूल्य के साथ ऐसे लाइसेंस शुल्क और कर्मचारियों द्वारा भुगतान की गई किराए की राशि के बीच का अंतर होगा। जहां तक अन्य कर्मचारियों का संबंध है, जिन्हें उनके संबंधित नियोक्ताओं द्वारा आवास प्रदान किया गया है, नियम कहता है कि किराया-मुक्त आवास का मूल्य वेतन का दस प्रतिशत होगा यदि आवास कुछ शहरों में हैं और यदि आवास अन्य शहरों में हैं, तो वेतन का 7.5 प्रतिशत और कुछ नहीं। नियम में आगे यह प्रावधान किया गया है कि अन्य कर्मचारियों के संबंध में, रियायत का मूल्य, जैसा भी मामला हो, वेतन के 10 प्रतिशत या 7.5 प्रतिशत और वास्तव में भुगतान की गई किराए की राशि के बीच का अंतर होगा। उचित किराये के मूल्य के निर्धारण की कोई गुंजाइश नहीं है। उचित किराये के मूल्य की अवधारणा को या तो सामान्य किराए के आधार पर या इलाके में उपलब्ध बाजार किराए के आधार पर या नगरपालिका मूल्यांकन के आधार पर समाप्त कर दिया गया है।

न्यायालय ने आगे कहा कि बाजार के साथ तुलनीय किराया हमेशा उचित या मानकीकृत किराए से अधिक होगा। चूंकि नया नियम 'उचित किराया', 'सामान्य किराया' या 'मानक किराया' प्रदान नहीं करता है,

उक्त अवधारणाओं में से कोई भी आकर्षित या लागू नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने अंत में निष्कर्ष निकाला; "सामान्य परिस्थितियों में, विधानमंडल द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा का शुद्ध, सरल और व्याकरणिक अर्थ यह समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि विधानमंडल का क्या इरादा है। यदि विधानमंडल का इरादा था कि 'किराया' शब्द का

अर्थ जैसा कि उपखंड (ii) में उपयोग किया गया है। अधिनियम की खंड 17 का खंड (2) वैसा ही होगा जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, विधानमंडल उसी खंड में इसका उपयोग कर सकता था। विधानमंडल ने अधिनियम की खंड 17 के खंड (2) में उपखंड (ii) को पेश करने के बाद लाया। अधिनियम की खंड 17 के खंड (2) का उपखंड (i): ये दो उपखंड इसे अलग-अलग नहीं पढ़ा जाना चाहिए। उन्हें एक साथ पढ़ने का इरादा था और यदि एक साथ पढ़ा जाए, तो यह बहुत स्पष्ट हो जाता है, और जैसा कि पहले भी किया गया था और वर्तमान में भी किया गया था, कि विधानमंडल किराया-मुक्त आवास के मूल्य और वास्तव में भुगतान किए गए किराए के बीच के अंतर की एक सरल गणना करके रियायत के मूल्य पर पहुंचने के उद्देश्य से किराया-मुक्त आवास का मूल्य निर्धारित करना चाहता था। "

*श्री परासरन* ने भी हमारा ध्यान *बी. एच. ई. आई. कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ* (2003) 261 आईटीआर 15 (कांत) में आमंत्रित किया था। न्यायालय ने माना की नियम 3 के साथ पठित खंड 17 (2) (vi) के आलोक में फ्रिंज सुविधाएँ को टकराओ के रूप मे मानने के प्रावधान को न तो संविधान के *अधिकारातीत* के रूप मे माना जा सकता है और न ही नियम 3 को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है की विधायिका द्वारा शक्तियों का अत्यधिक प्रतिनिधिमंडल कार्यकारी था।

*बी. एच. ई. एल. कार्यकारी/अधिकारी संघ और अन्य बनाम डी. आयकर आयुक्त और अन्य,* (2004) 264 आईटीआर 390 में मद्रास उच्च न्यायालय के एक निर्णय का भी संदर्भ दिया गया था। कर्मचारियों की ओर से उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि जनसंख्या के आकार के आधार पर भेद का कोई औचित्य नहीं था और 2001 में संशोधित नियम 3 अधिकार *अधिकारातीत* था। इस तर्क को नकार दिया गया।

श्री परासरन ने अखिल भारतीय स्तर पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा 1 सितंबर, 2004 को पारित एक आदेश पर भी भरोसा किया। *स्टेट बैंक ऑफ इंदौर अधिकारी समन्वय समिति और अन्य बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अन्य*, (2004) 186 सीटीआर 649 (एमपी)। उस मामले में, न्यायालय का ध्यान *अधिकारी संघ , भिलाई स्टील प्लांट* और उसके बाद कलकत्ता और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों और राजस्थान

और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों द्वारा विपरीत दृष्टिकोण रखने वाले निर्णयों की ओर आकर्षित किया गया था।

परस्पर विरोधी विचारों को पीठ में रखते हुए, न्यायालय ने मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। अपीलार्थियों की शिकायत यह है कि संशोधित नियम 3 में निर्धारिती को निर्धारण अधिकारी को यह समझाने का अवसर देने का प्रावधान नहीं है कि नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए आवास के संबंध में कर्मचारी को कोई "रियायत" नहीं दिखाई गई थी। श्री साल्वे ने प्रस्तुत किया कि नियम लागू होगा और कर कटौती का दायित्व केवल तभी उत्पन्न होगा जब किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में "रियायत" दिखाई गई हो और यह अधिनियम के तहत "आवश्यक" है, प्राधिकरण को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि खंड 17 (2) (ii) आकर्षित है। किसी भी प्रावधान की अभाव जो निर्धारिती को निर्धारण अधिकारी को यह दिखाने में सक्षम बनाती है कि यह 'रियायत' नहीं थी और इसलिए, 'शर्त' *अधिकारातीत* और असंवैधानिक था । ऐसी स्थिति में, कानून की अदालत के प्रावधान की शाब्दिक व्याख्या को नहीं अपना सकती है, लेकिन "रीडिंग डाउन" सूत्र को लागू करके, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करते हुए इसकी वैधता को बनाए रख सकती है।

'नीचे पढ़ने' का सिद्धांत संवैधानिक कानून के इस क्षेत्र में सर्वविदित है - कॉलिन हावर्ड ने अपनी प्रसिद्ध कृति "ऑस्ट्रेलियाई संघीय संवैधानिक कानून" में कहा

है;

नीचे पढ़ने से यह सिद्धांत लागू होता है कि जहां तक उचित रूप से ऐसा करना संभव है, कानून को शक्ति के भीतर होने के रूप में माना जाना चाहिए। इसका व्यावहारिक प्रभाव है कि जहां एक अधिनियम व्यक्त किया जाता है

एक ऐसी सामान्यता की भाषा में जो इसे सक्षम बनाती है, यदि शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए, प्रासंगिक विधायी शक्ति से परे मामलों पर लागू करने का तो न्यायालय इसे अधिक सीमित अर्थों में समझेगा ताकि इसे शक्ति के भीतर रखा जा सके।

जैसा कि इस न्यायालय ने *बिक्री कर आयुक्त, मध्य प्रदेश और अन्य बनाम राधाकृष्णन और अन्य*, [1979] 2 एस. सी. सी. 249 मामलों में कहा है। विचार करने में किसी कानून की वैधता के लिए अनुमान हमेशा अधिनियमता के पक्ष में होता है और यह बोझ उस व्यक्ति पर होता है जो यह दिखाने के लिए उस पर हमला करता है कि अधिनियम सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। एक अधिनियम की संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए, एक अदालत सामान्य ज्ञान, अभिलेख , प्रस्तावना, समय का इतिहास, विधान का उद्देश्य और अन्य सभी मामलों पर विचार कर सकती है और तथ्य जो प्रासंगिक हैं। यह हमेशा माना जाना चाहिए कि विधानमंडल अपने लोगों की आवश्यकता को समझता है और सही ढंग से समझता है और यह कि भेदभाव, यदि कोई हो, तो पर्याप्त आधारों और विचारों पर आधारित है। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि संवैधानिक अयोग्यता से बचने के लिए अदालतों को एक उदार व्याख्या आदेश में उचित ठहराया जाएगा। प्राधिकरण को बहुत व्यापक और विस्तृत शक्तियां प्रदान करने वाले प्रावधान को संवैधानिक सीमाओं के भीतर शक्ति के प्रयोग के विधायी इरादे के अनुरूप माना जा सकता है। जहां कोई अधिनियम मौन है या निष्क्रिय है, वहां अदालत निष्क्रिय को पार करने और एक ऐसे निर्माण को अपनाने का प्रयास करेगी जो उस सामग्री से अलग हुए बिना संवैधानिकता की ओर झुकेगा जिसमें अधिनियम बुना गया है। इन सिद्धांतों ने प्रावधानों को 'पढ़ने' के नियम को जन्म दिया है यदि यह कानून की वैधता को बनाए रखने के लिए आवश्यकबन जाता है।

कई मामलों में, अदालतों ने 'पढ़ने' के सिद्धांत को आह्वान और लागू किया है। और अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

*ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम*, [1985] 3 एस. सी. सी. 545: ए. आई. आर. (1986) एस. सी. 180 [1985] पूरक 2 एस.सी. आर. 51, उच्चतम न्यायालय से बॉम्बे नगर निगम अधिनियम, 1888 की खंड 314 की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था, जिसने आयुक्त को *बिना किसी सूचना* के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का अधिकार दिया था। यह तर्क दिया गया कि यह प्रावधान मनमाना, अनुचित और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करने वाला था।

न्यायालय ने कहा कि प्रावधान को *अपने अधिकार में रखते हुए* सिद्धांत को 'पढ़ना' और उसमें *दूसरे पक्ष को भी सुनो;*

" अपने उचित परिप्रेक्ष्य में माने जाने पर, खंड 314 एक सक्षम प्रावधान की प्रकृति में है न कि एक बाध्यकारी चरित्र की। यह आयुक्त को, उचित मामलों में प्रस्तावित कार्यवाई से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को पहले से सूचित करने की आवश्यकता को समाप्त करने में की अनुमति देता है। इसकी आवश्यकता नहीं है और इसका अर्थ यह नहीं पढ़ा जा सकता है कि किसी दी गई स्थिति से संबंधित प्रासंगिक परिस्थितियों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए, आयुक्त को पूर्व सूचना जारी किए बिना अतिक्रमण को हटाने का कारण बनना चाहिए। निर्माण का प्राथमिक नियम यह है कि कानून की भाषा को उसका स्पष्ट और स्वाभाविक अर्थ प्राप्त होना चाहिए। क्या खंड 314 में प्रावधान है कि आयुक्त, बिना किसी सूचना के, प्रस्तावित कार्रवाई से प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों को नोटिस के बिना अतिक्रमण को हटा सकता है। यह आदेश नहीं देता है कि आयुक्त, बिना किसी सूचना के, अतिक्रमण को हटाने का कारण बनेगा। इसे अलग तरीके से रखते हुए, खंड 314

में कहा गया है -

आयुक्त के विवेकाधिकार के अनुसार अतिक्रमण को सूचना के साथ या बिना सूचना के हटाया जा सकता है। उस विवेकाधिकार का अभ्यास में उचित तरीके से होना चाहिए ताकि संवैधानिक जनादेश का पालन किया जा सके कि सार्वजनिक कार्य के निष्पादन के साथ प्रक्रिया निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए।" *हमें इसके पक्ष में झुकना चाहिए। क्योंकि यह व्याख्या कानून की वैधता को बनाए रखने में मदद करता है। खंड 314 को पढ़ने से पहले नोटिस जारी करना न करने का आदेश मिलता है अतिक्रमण को हटाने से कानून अमान्य हो जाएगा।*"

(जोर दिया गया)

*सलेम अधिवक्ता बार संघ बनाम भारत संघ*, [2005] 6 एस. सी. सी. 344, इस न्यायालय को स्थगन से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा प्रभावी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 17 में कुछ संशोधनों की संवैधानिक वैधता

पर विचार करने का अवसर मिला था। संशोधनों में से एक में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी मुकदमे के दौरान किसी पक्ष को तीन बार से अधिक स्थगन नहीं दिया जाएगा। यद्यपि यह एक स्पष्ट प्रावधान था, इस न्यायालय ने कहा कि पक्ष के नियंत्रण से परे चरम मामले या असाधारण परिस्थितियां हो सकती हैं जो उसे स्थगन की मांग करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। गंभीर बीमारी, दुर्घटना, अचानक अस्पताल में भर्ती होना, भूकंप, दंगे, सुनामी आदि या तो *प्रमुख* या अप्रत्याशित घटनाएँ हैं जो किसी पक्ष को स्थगन की माँग करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। शाब्दिक व्याख्या प्रावधान को मनमाना, अनुचित और अधिकार *अधिकारातीत* बना सकती है। इसलिए, न्यायालय ने कहा कि "आदेश 17, नियम 1, के परंतुक को संविधान के अनुच्छेद 14 के दोष से बचाने के लिए, इसे पढ़ना आवश्यक है ताकि इसे अत्यधिक कठिन मामलों में न्यायालय के विवेकाधिकार से दूर न किया जा सके।"

लेकिन यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि कानून का प्रावधान स्पष्ट है, तो भाषा स्पष्ट और व्याख्या अधिक के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है। एक से अधिक निर्माण, इसे जैसा है वैसा ही पढ़ना होगा। उस मामले में, प्रावधान कानून का परीक्षण कानून या संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों की कसौटी पर किया जाना चाहिए और यह अदालत के लिए खुला नहीं है कि वह अधिनियम को 'अधिनियम के उद्देश्यों को विकृत करने' के बिंदु तक ले जाकर इसे अधिकार *अधिकारातीत* घोषित करने से बचाने की दृष्टि से 'पढ़ने' के 'सिद्धांत" का आह्वान करे।

इस प्रकार, *मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ*, [1980] 3 एस. सी. सी. 625, संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 31सी की वैधता, संविधान के भाग IV में निर्देशात्मक सिद्धांतों कोप्रभावी बनाने वाले कानूनों को चुनौती देने से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इस अदालत में पूछताछ की गई। भारत संघ की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि न्यायालय सी चुनौती को केवल ऐसे कानूनों तक सीमित करके "पढ़ने" के सिद्धांत को लागू कर सकता है जो संविधान की "मूल संरचना" का उल्लंघन नहीं करेंगे।

विवाद को नकारते हुए और बहुमत के लिए बोलते हुए, सी जे चंद्रचूड़ ने कहा; "यदि संसद ने असीमित शक्ति का प्रयोग करने का स्पष्ट इरादा व्यक्त किया है, तो उस शक्ति के आयाम को कम करना अस्वीकार्य है ताकि इसे सीमित किया जा सके। पढ़ने के सिद्धांत को विधायिका के स्पष्ट इरादे के विरोध में लागू या लागू नहीं किया जा सकता है। हम मानते हैं कि संवैधानिक कानून के इतिहास में, कोई संवैधानिक नहीं है संशोधन को हमेशा इसके कहने और इरादे के बिल्कुल विपरीत अर्थ के लिए पढ़ा गया है। वास्तव में, इस तर्क को प्रतिग्रहण करना करना कि हमें अनुच्छेद 31सी को पढ़ना चाहिए, ताकि इसे *केशवानंद* भारती में बहुमत के निर्णय के अनुपात के अनुरूप बनाया जा सके, अनुच्छेद 31सी के घोषित उद्देश्य को नष्ट करना है जैसा कि "कुछ कानूनों की बचत" शीर्षक द्वारा इंगित किया गया है, जिसके तहत अनुच्छेद 31ए, 31बी और 31सी को समूहीकृत किया गया है। *चूंकि अनुच्छेद 31सी में संशोधन निर्विवाद रूप से एक विशेष विवरण के कानूनों को पारित करने के लिए विधानसभाओं को सशक्त बनाने की दृष्टि से किया गया था, भले ही वे कानून अनुच्छेद एफ 14 और 19 के अनुशासन का उल्लंघन करते हों, हमें यह मानना असंभव लगता है कि हमें अभी भी अनुच्छेद 31सी को असंवैधानिकता की चुनौती से बचाना चाहिए।*

(जोर दिया गया)

इसी तरह *दिल्ली परिवहन निगम बनाम. डी. टी. सी. मजदूर कांग्रेस और अन्य*, [1991 ] पूरक 1 एस.सी. सी. 600, दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकरण (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) विनियम, 1952 की 'सेवा समाप्ति' से संबंधित विनियम 9 (बी) की वैधता और अधिकार को चुनौती दी गई थी। इसने निगम के स्थायी कर्मचारियों की सेवा को एक महीने के नोटिस पर समाप्त करने या बिना किसी जांच के नोटिस के बदले में भुगतान करने का प्रावधान किया। प्रावधान को चुनौती दी गई थी। संविधान के अधिकार *अधिकारातीत* होना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन और अनुबंध अधिनियम 1872 की खंड 23 के साथ असंगत होना। इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए प्रश्नों में से एक यह था कि क्या यह अदालत के लिए 'पढ़ने' के सूत्र को लागू करने और इसमें प्राकृतिक न्याय का आयात करके प्रावधान को बचाने के लिए खुला होगा। बहुमत (4:1) ने इस प्रावधान को 'हेनरी VIII खंड' के रूप में वर्णित करके और 'पढ़ने के सिद्धांत' को लागू करने से इनकार करके इसे

अधिकार अधिकारातीत और असंवैधानिक ठहराया। इसने अभिनिर्धारित किया कि विनियम की भाषा स्पष्ट, सुस्पष्ट और सुव्यक्त थी और न्यायालय के लिए विनियमों द्वारा अभिप्रेत किसी चीज़ को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पढ़ने का सिद्धांत लागू किया जा सकता है यदि अधिनियम मौन, अस्पष्ट है या एक से अधिक व्याख्या की अनुमति देता है। लेकिन जहां अभिव्यक्त और स्पष्ट रूप से कुछ कार्रवाई करने का आदेश देता है, वहां न्यायालय का कार्य इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या करना और उसमें कुछ भी जोड़े, बदले या घटाए बिना अंतर अधिकार या *अधिकारातीत* अधिकार घोषित करना है।

जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं, 2001 में इसके संशोधन से पहले नियम 3 पूरी तरह से अलग था। यह रियायत की गणना की विधि से संबंधित था। "उचित किराये के मूल्य" की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए। नियम 3 के सिद्धांत और वाक्यांश के आलोक में, नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने निर्धारिती को निर्धारण अधिकारी को संतुष्ट करने का अवसर प्रदान किया कि कर्मचारी से वसूल किए जाने वाले किराए को 'रियायत' नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह 'उचित किराया' था। उचित किराया ',' बाजार किराया 'या' मानक किराया'। जब नियम में संशोधन किया जाता है और "उचित किराये के मूल्य" की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाता है और एकमात्र तरीका जो अपनाया गया है वह शहर की आबादी के आधार पर किराए की गणना करना है, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण का इरादा निर्धारिती को निर्धारण अधिकारी को यह समझाने का अवसर देना था कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी से वसूल किया गया किराया रियायत की प्रकृति का नहीं था। न ही कोई एफ अदालत, व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा, निर्धारिती को ऐसा अवसर प्रदान करेगी ताकि वह निर्धारण अधिकारी को यह समझाने में सक्षम हो कि निर्धारित किराया अधिनियम की खंड 17 (2) (ii) के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए यह एक शर्त नहीं थी। इसलिए हम श्री साल्वे के तर्क को प्रतिग्रहण करना करने और नियम 3 में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आयात की अनुमति देने में असमर्थ हैं।

इसलिए सवाल यह है कि क्या ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद14 के अधिकार से *अधिकारातीत* है। हालाँकि इस मुद्दे पर इस न्यायालय का कोई सीधा निर्णय नहीं है, लेकिन कुछ उच्च न्यायालयों ने इस प्रश्न पर विचार किया है। *बीएचईएल कर्मचारी संघ बनाम*

*भारत संघ*। ( 2003 ) 261 आईटीआर 15 (कर), संशोधित नियम 3 की वैधता को चुनौती दी गई थी। हालाँकि, उस मामले में, न्यायालय फ्रिंज लाभों (जो पूरी तरह से एक अलग आधार पर खड़े हैं) से संबंधित था। लेकिन तर्क "यह था कि विधानमंडल द्वारा अत्यधिक शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, इसलिए, कार्यपालिका और प्रावधान मूल अधिनियम के अधिकार क्षेत्र *अधिकारातीत* थे और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था।

इस मुद्दे पर कई मामलों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि अधिनियम के खंड 295 ने एक उच्च पदाधिकारी यानी केंद्रीय को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी. बी. डी. टी.), केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन यह भी देखा गया कि बोर्ड में भारत सरकार के बहुत उच्च पदाधिकारी शामिल थे, जिन्हें देश में कर लगाने के लिए परिकल्पित नीति के बारे में गहरी जानकारी होने की उम्मीद थी। जब ऐसे विशेषज्ञ निकाय को शक्ति प्रदान की गई और प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद, उसने निर्णय लिया, तो इसे गैरकानूनी या अनुचित नहीं कहा जा सकता था। विधायी नीति अधिनियम और नियम की खंड 17 में परिलक्षित हुई थी। प्राधिकरण बनाना, केवल आवश्यक के आधार पर उक्त नीति को लागू किया संसद द्वारा किए गए विधायी कार्य। इसलिए, न्यायालय ने अत्यधिक प्रत्यर्पण के तर्क को नकार दिया। किसी भी कठिनाई या कष्ट में व्यक्तिगत मामला या किसी विशेष व्यक्ति के लिए नियम को अधिकार *अधिकारातीत* या असंवैधानिक नहीं करेगा।

इसी तरह का दृष्टिकोण राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा *आदित्य सीमेंट स्टाफ क्लब बनाम भारत संघ,* (2004) 266 आई. टी. आर. 70 में लिया गया था।

विवादित आदेश में झारखंड के उच्च न्यायालय ने उचित वर्गीकरण के रूप में चार लाख से कम और चार लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के बीच वर्गीकरण इसलिए यह माना गया कि नियम मनमानेपन के दुष्प्रभाव से ग्रस्त नहीं था। इसी तरह, उच्च न्यायालय ने कलकत्ता ने दो मामलों में विवादित आदेश में नियम की वैधता को बरकरार रखा। *अन्य बातों के साथ साथ* देखते हुए कि रियायत का निर्धारण करते समय, नियम स्वयं को संबोधित करता है प्रासंगिक और व्यापक विचारों के लिए और इस तरह के प्रावधान को मनमाना या अधिकार *अधिकारातीत* नहीं माना जा सकता है।

हमारी राय में, श्री परासरन की प्रस्तुति, अतिरिक्त विद्वान सॉलिसिटर जनरल को स्वीकार किया जाना चाहिए कि जब "निष्पक्ष" की अवधारणा किराया "," बाजार किराया "," उचित किराया "या" मानक किराया "अब प्रासंगिक नहीं है या प्रश्न का निर्णय लेने में, यह विधानमंडल के लिए खुला था कि वह "रियायत" गणना के लिए विधि प्रदान करने के लिए नियम बनाने वाले प्राधिकरण को सशक्त करे। हमारा आगे यह विचार है कि जो मानदंड अपनाया गया था चार लाख से कम और चार लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के साथ व्यवहार करने में नियम बनाने वाले प्राधिकरण को मनमाना या मनमाना नहीं कहा जा सकता है। शहर की आबादी के आधार पर अनुचित और किराया तय नहीं किया जा सकता है और न ही न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप कर सकता है। उक्त तर्क कोई सार नहीं है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

लेकिन हमारी राय में, अधिनियम की खंड 17 (2) की प्रयोज्यता का मौलिक प्रश्न अभी भी बना हुआ है। यह नहीं कहा जा सकता है कि खंड 17 (2) केवल तभी लागू होगी जब 'शर्त' हो। निर्विवाद रूप से, 'अनुलाभ' की परिभाषा समावेशी प्रकृति की है और इसमें कई मामलों को शामिल किया गया है। खंड (i) से (vii) में खंड 17 (2) (ii) घोषित करती है कि किसी भी का मूल्य " कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में रियायत "आवश्यक" होगी। फिर भी यह नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को प्रदान किए गए किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में एक "रियायत"

"रियायत" शब्द को न तो अधिनियम में परिभाषित किया गया है और न ही नियमों में। संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रियायत "एक ऐसी चीज है जिसे स्वीकार किया जाता है"; "एक मांग या प्रचलित मानक की मान्यता में किया गया एक इशारा", "व्यक्ति की एक निश्चित श्रेणी के लिए कीमत में कमी"। यह "एक अनुदान है; आमतौर पर सरकार द्वारा विशिष्ट विशेषाधिकारों के अनुदान पर लागू होता है, एक सरकार, निगम या अन्य प्राधिकरण द्वारा दिया गया विशेष विशेषाधिकार" (पी. आर. अय्यर; "एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन"। 2005 ; खण्ड. 1 ;पी 944 ) . यह "एक मांग या तर्क के रूप में स्वीकार करने या स्वीकार करने का कार्य है; कुछ स्वीकार किया गया; आमतौर पर एक मांग

को नियोजित करनाः दावा या अनुरोध ";" एक चीज प्राप्त हुई "। “एक अनुदान"। [भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम ठाणे नगर निगम; (1992) पूरक 1 ई एस. सी. सी. 480] "रियायत" "विशेषाधिकार" का एक रूप है [*वी. पेचिमेथु बनाम गौरमल*, [2001] 7 एस. सी. सी. 617]।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि खंड 17 (2) (ii) से पहले लागू किया जा सकता है या सेवा में लगाए जाने और नियम 3 के अनुसार रियायत की गणना करने से पहले, शक्ति का प्रयोग करने वाले प्राधिकरण को एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि यह एक रियायत है '। इस प्रकार, हमारे विचार में 'रियायत' एक आधार है। मौलिक या न्यायिक तथ्य न्यायक्षेत्र संबंधी तथ्य "एक ऐसा तथ्य है जो न्यायालय के समक्ष मौजूद होना चाहिए।

न्यायाधिकरण या प्राधिकरण किसी विशेष मामले पर अधिकार क्षेत्र ग्रहण करता है। एक अधिकारिता तथ्य वह है जिसका अस्तित्व या गैर-अस्तित्व किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करता है। यह वह तथ्य है जिस पर एक प्रशासनिक एजेंसी की कार्य करने की शक्ति निर्भर करती है। यदि क्षेत्राधिकार तथ्य मौजूद नहीं है, तो अदालत, प्राधिकरण या अधिकारी कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि कोई न्यायालय या प्राधिकरण गलत तरीके से इस तथ्य के अस्तित्व को मानता है, तो आदेश पर *सरशियोरेराई* द्वारा सवाल उठाया जा सकता है। अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि गलती से इस तरह के अस्तित्व को मानते हुए क्षेत्राधिकार तथ्य कोई भी प्राधिकारी स्वयं को ऐसा अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकता है जो वह अन्यथा यह संभव नहीं है।

*हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड* में यह कहा गया है;

> "जहाँ किसी न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र किसी विशेष स्थिति के अस्तित्व पर निर्भर है, वहाँ उस स्थिति का वर्णन किया जा सकता है। इस मुद्दे के गुण-दोष के लिए प्रारंभिक या संपार्श्विक के रूप में यदि किसी निम्न न्यायाधिकरण द्वारा जांच की शुरुआत में, उसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी जाती है, तो न्यायाधिकरण को यह तय करना होगा कि कार्रवाई करनी है या नहीं और वह प्रारंभिक या संपार्श्विक मुद्दे पर निर्णय दे सकता है, लेकिन वह निर्णय निर्णायक नहीं है।“

इस प्रकार अधिकार क्षेत्र तथ्य का अस्तित्व सीमित अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए *अनिवार्य रूप* से गैर या शर्त पूर्ववर्ती है।

*राजा आनंद ब्रह्मा शाह बनाम यू. पी. राज्य और अन्य*, ए आई आर (1967) एससी 1081: [1967]1 एस. सी. आर. 362, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की खंड 17 की उप-खंड (1) ने राज्य सरकार को कलेक्टर को अधिग्रहण करने का अधिकार दिया। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक 'किसी भी अपशिष्ट या कृषि योग्य भूमि' का कब्जा, यहां तक कि पुरस्कार की अनुपस्थिति में अधिनियम की खंड 17(1) के तहत शक्ति के कथित प्रयोग में अपीलकर्ता की भूमि का कब्जा छीन लिया गया था। अपीलकर्ता अन्य बातों के साथ साथ इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भूमि का उपयोग मुख्य रूप से जुताई और फसलें उगाने के लिए किया जाता था और यह 'बंजर भूमि' नहीं थी, जो खेती या निवास के लिए अनुपयुक्त थी। यह आग्रह किया गया था कि चूंकि प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र इस तथ्य के प्रारंभिक निष्कर्ष पर निर्भर करता है कि भूमि 'बंजर भूमि' थी, इसलिए उच्च न्यायालय को यह *सरशियोरेराई* के लिए एक प्रमाण पत्र की कार्यवाही में अधिकार था कि तथ्य का निष्कर्ष सही था या नहीं।

विवाद को कायम रखना और राज्य के निर्देश की घोषणा करना इस न्यायालय ने कहा कि सरकार अधिकार *अधिकारातीत* है।

> "हमारी राय में, एस द्वारा लगाई गई शर्त 17 (1) यह एक ऐसी शर्त है जिस पर राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र निर्भर करता है और यह स्पष्ट है कि भूमि के स्वरूप के बारे में प्रश्न का गलत निर्णय लेने से राज्य सरकार कलेक्टर भूमि का कब्जा लेने का निर्देश धारा 17 (1) मे देने के लिए खुद को अधिकार क्षेत्र नहीं दे सकती है। *अधिनियम से यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां किसी प्रशासनिक प्राधिकरण की अधिकार क्षेत्र तथ्य के प्रारंभिक निष्कर्ष पर निर्भर करती है, वहां उच्च न्यायालय अपने स्वतंत्र निर्णय पर यह सरशियोरेराई का हकदार है कि तथ्य का निष्कर्ष सही है या नहीं।* "(जोर दिया गया)

*म.प्र. एवं अन्य राज्य बनाम डी. के. जादव*, एआईआर (1968) एससी 1186: (1968) 2 एससीआर 823. प्रासंगिक क़ानून ने भूमि, जंगल, पेड़, टैंक सहित सभी जागीरों को

समाप्त कर दिया और उन्हें राज्य में निहित कर दिया। हालाँकि, इसमें कहा गया है कि कब्जे वाली भूमि पर सभी तालाबों, कुओं और इमारतों को इस सूची से बाहर रखा गया था। अधिनियम के प्रावधान मे इस न्यायालय ने माना कि यह प्रश्न कि क्या तालाब, कुएं आदि 'कब्जे वाली भूमि' पर थे या 'खाली भूमि' पर थे, एक अधिकार क्षेत्र था। तथ्य और उस तथ्य के निर्धारण पर, प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र निर्भर करेगा।

न्यायालय ने *व्हाइट और कॉलिन्स बनाम स्वास्थ्य मंत्री* (1939) 2 के बी 838: 108 एल. जे. के. बी.768, में एक निर्णय पर भरोसा किया के जिसमें जिसमें एक प्रश्न पर बहस हुई थी कि क्या न्यायालय के पास तथ्य के प्रश्न पर प्रशासनिक प्राधिकरण के निष्कर्ष की समीक्षा करने का अधिकार क्षेत्र था। प्रासंगिक अधिनियम ने स्थानीय प्राधिकरण को श्रमिक वर्गों के आवास के लिए अनिवार्य रूप से भूमि अधिग्रहण करने में सक्षम बनाया लेकिन यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि कोई भी भूमि अधिग्रहित नहीं की जा सकती थी जो अनिवार्य खरीद की तारीख पर उद्यान, उद्यान या मनोरंजन स्थल का हिस्सा थी। अनिवार्य खरीद का आदेश दिया गया था जिसे मालिक द्वारा चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि भूमि *उद्यान* का एक हिस्सा है। मंत्री ने सार्वजनिक जांच का निर्देश दिया और प्रस्तुत अभिलेख  के आधार पर आदेश की पुष्टि की।

मंत्री के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करते हुए और आदेश को रद्द करते हुए, अपील की अदालत ने कहा;

> "ध्यान में रखने वाली पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदेश देने की अधिकारिता तथ्य के निष्कर्ष पर निर्भर करती है; क्योंकि, जब तक कि भूमि को किसी उद्यान का हिस्सा नहीं माना जा सकता है या सुविधा या सुविधा के लिए आवश्यक नहीं माना जा सकता है, तब तक नगर परिषद में आदेश बनाने या मंत्री द्वारा पुष्टि करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ऐसे मामले में यह लगभग स्पष्ट प्रतीत होता है कि न्यायालय को इस बात पर विचार करें कि क्या आदेश देने या पुष्टि करने का अधिकार क्षेत्र उस महत्वपूर्ण निष्कर्ष की समीक्षा करने का हकदार होना चाहिए जिस पर अधिकार क्षेत्र का अस्तित्व निर्भर करता है। यदि ऐसा नहीं होता,तो न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार भ्रामक होता।

[*रेक्स बनाम शोरेडिच मूल्यांकन समिति*] (1910) 2 KB 859: 80 एलजे के. बी. 185] भी देखें।;

आयकर अधिनियम, 1922 के तहत एक प्रश्न रज़ा टेक्सटाइल्स लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी, रामपुर, [1973] 1 एस. सी. सी. 633 ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 1362 में उठा। उस मामले में, आईटीओ ने एक्स को कर की एक निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया एक्स का तर्क दिया कि वह एक अनिवासी फर्म नहीं था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने एक्स को गैर-ए निवासी फर्म के रूप में माना और स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालांकि, खण्ड पीठ ने आदेश को यह कहते हुए दरकिनार कर दिया कि "आईटीओ के पास किसी भी तरह से प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र था। यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकारी ने निवास के इस प्रश्न पर गलत निर्णय लेकर अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया। एक्स ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया।

अपील को अनुमति देते हुए और खण्ड पीठ के आदेश को

दरकिनार करते हुए इस न्यायालय ने कहा;

> " ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय पीठ इस धारणा में थी कि आय-कर अधिकारी इस तथ्य का एकमात्र न्यायाधीश था कि क्या विचाराधीन फर्म निवासी थी या अनिवासी। इस निष्कर्ष में, हमारे राय पूरी तरह से गलत है। कोई भी प्राधिकरण, बहुत कम एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण, किसी अधिकार क्षेत्र के तथ्य को गलत तरीके से तय करके खुद को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकता है। यह सवाल कि क्या अधिकार क्षेत्र के तथ्य का सही निर्णय लिया गया है या नहीं, एक ऐसा सवाल है जो उच्च न्यायालय द्वारा *सरशियोरेराई* के लिए एक आवेदन में जांच के लिए खुला है। यदि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मामले में किया है, कि आय-कर अधिकारी ने किसी अधिकार क्षेत्र संबंधी तथ्य का गलत निर्णय लेकर अधिकार क्षेत्र को पकड़ लिया था, तो निर्धारिती ने कहा थाः उसके द्वारा प्रार्थना की गई *सरशियोरेराई* रिट के लिए हकदार है। *यह सोचना समझ से परे है कि आयकर अधिकारी जैसा अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण गलती*

*से किसी अधिकार क्षेत्र के तथ्य का निर्णय ले सकता है और उसके बाद किसी नागरिक पर शुल्क लगाने के लिए आगे बढ़ सकता है।"* ( जोर दिया गया)

उपरोक्त निर्णयों से, यह स्पष्ट है कि 'क्षेत्राधिकार' का अस्तित्व तथ्य 'शक्ति के प्रयोग के लिए अनिवार्य है। यदि अधिकारिता संबंधी तथ्य मौजूद है, प्राधिकारी मामले को आगे बढ़ा सकता है और कानून के अनुसार उचित निर्णय ले सकता है। एक बार जब प्राधिकरण के पास 'क्षेत्राधिकार तथ्य' के अस्तित्व के मामले में अधिकार क्षेत्र हो जाता है, तो वह 'मुद्दे में तथ्य' या 'न्यायिक तथ्य' तय कर सकता है। 'मुद्दे में तथ्य' या 'न्यायिक तथ्य' पर एक गलत निर्णय प्राधिकरण का निर्णय अधिकार क्षेत्र के बिना या कमजोर नहीं करेगा बशर्ते अधिकार क्षेत्र के अस्तित्व के रूप में आवश्यक या मौलिक तथ्य मौजूद हो।

हमारी राय में, श्री साल्वे का समर्पण अच्छी तरह से स्थापित और योग्य है यह स्वीकार किया जाए कि अधिनियम की खंड 17 की उप-खंड (2) के खंड (ii) के तहत "रियायत" एक "क्षेत्राधिकार तथ्य" है। यह केवल तभी होता है जब किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को प्रदान किए गए किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में 'रियायत' होती है कि इस तरह की रियायत की गणना कैसे की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, रियायत एक 'क्षेत्राधिकार तथ्य' है; राशि के निर्धारण की विधि 'तथ्य जारी' या 'न्यायिक तथ्य' है। यदि एक निर्धारिती का तर्क है कि कोई रियायत नहीं है, प्राधिकरण को उक्त प्रश्न का निर्णय करना होगा और एक निष्कर्ष खंड करना होगा कि क्या रियायत है और मामला अधिनियम की धारा 17 (2) (ii) के अंतर्गत आता है। इसके बाद ही नियम प्राधिकरण निर्धारिती के दायित्व की गणना करने के लिए आगे बढ़ सकता है। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, इस कानूनी स्थिति के बावजूद कि नियम 3 *अधिकार के भीतर* है, वैध है और इसके प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है। अधिनियम की खंड 17 (2) (ii) के तहत मूल अधिनियम अभी भी निर्धारिती के लिए खुला है। यह तर्क देना कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किए गए आवास के मामले में कोई 'रियायत' नहीं है और इसलिए मामला अधिनियम की खंड 17 (2) (ii) की हानी के दायरे में नहीं आता है।

इस मामले का एक और पहलू है जो महत्वपूर्ण है और इसका प्रश्न पर असर पड़ता है। हम निर्णय के पूर्व भाग में खंड 17 (2) (ii) निकाल चुके हैं। इसमें कोई 'डीमिंग क्लॉज' नहीं है कि एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि कोई कर्मचारी चार लाख की आबादी वाले शहरों में अपने वेतन के 10 प्रतिशत या अन्य शहरों में 7.5 प्रतिशत से कम किराया दे रहा है, इसे अधिनियम के अर्थ के भीतर 'रियायत' माना जाना चाहिए और ऐसे कर्मचारी को 'किराए के भुगतान में शर्त' के रूप में 'रियायत' प्राप्त करने वाला माना जाना चाहिए। एक नियोक्ता कई कारणों से अपने कर्मचारियों को आवासीय आवास प्रदान कर सकता है। यह भी संभव है कि कर्मचारी आवास/कॉलोनियां/आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें या केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को रियायती दर पर भूमि प्रदान कर सकती है। इस मामले का एक और पहलू है जो महत्वपूर्ण है और नियोक्ता द्वारा वसूल किए जाने वाले किराए की राशि,यदि कोई हो, सहित उपयुक्त शर्तें लागू होगी। श्री साल्वे ने कुछ निर्णयों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान की गई आवासीय सुविधा को आयकर कानूनों के अर्थ के भीतर 'आवश्यक' नहीं माना गया था।

श्री साल्वे ने *अलेक्जेंडर टेनेंट बनाम रॉबर्ट स्मिथ* ,(1892) एसी 150 (एचएल) में एक निर्णय पर भरोसा रखा। वहाँ, अपीलकर्ता जो मॉन्ट्रोस में बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के लिए एक एजेंट था, को उसके द्वारा आवास प्रदान किया गया था। नियोक्ता अपने कर्तव्य के अंश के रूप में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि वह बैंक हाउस में रहने के लिए एजेंट के रूप में अपने कर्तव्य के हिस्से के रूप में बाध्य था क्योंकि रोजगार की प्रकृति के लिए आवश्यक था कि वह अपने स्वयं के एक अलग निवास पर कब्जा करने के बजाय अपने स्वामी के निवास घर या व्यवसाय-परिसर में रहे। न्यायालय के अनुसार, "इस तरह के व्यवसाय को अपीलार्थी की आय का हिस्सा नहीं माना जा सकता है"। उन्होंने अपने कर्तव्य के एक हिस्से के रूप में बैंक हाउस पर कब्जा कर लिया। *यह देखा गया कि स्थिति को मास्टर ऑफ शिप से अलग नहीं किया जा सकता था, जिसे तैरते समय घर के किराए की लागत से बख्शा गया था। उसका केबिन, उस कारण से उसकी आय का हिस्सा नहीं बन जाता है।* ( जोर दिया गया )

*टायरर बनाम स्मार्ट*, [1978]। औल ई. आर. 1089: [1978] 1 डब्ल्यूएलआर 415; एक निजी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बाजार मूल्य से कम मूल्य पर शेयर खरीदने का तरजीही अधिकार दिया और अदालत के समक्ष सवाल यह था कि क्या यह कर योग्य लाभ या सुविधा का गठन कर सकता है। अपील न्यायालय ने अलेक्जेंडर टेनेंट में निर्धारित सिद्धांत को दोहराया औ कहा कि यदि एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को उनकी वफादारी को प्रोत्साहित करने के लिए आकर्षित करने के लिए कुछ किया जाता है, तो इसे प्रदान की गई सेवाओं के लिए पुरस्कार के रूप में नहीं माना जा सकता है और यह एक कर योग्य शर्त नहीं बन सकती है। एक लाभ या सुविधा जो नियोक्ता के वाणिज्यिक हित को आगे बढ़ाती है, अपने आप में आवश्यक नहीं होगी। आवास की ऐसी सुविधा संतोषजनक कार्यबल के साथ नियोक्ता के वाणिज्यिक हित को आगे बढ़ाती है। लेकिन ऐसे आवास के लिए, उपलब्ध नहीं होता। ऐसे मामलों में, जैसे डॉक्टर/अधीक्षक/रेक्टर/प्रोफेसर/शिक्षक/गृहपति/गृहमाता, नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए आवास में रहना आदि 'रियायत' से अधिक 'मजबूरी' हो सकती है।

श्री साल्वे ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में, यह अधिकारियों के लिए है, विषय पर कर लगाने की मांग, कर देयता स्थापित करने के लिए और यह इसके लिए नहीं है यह साबित करने के अधीन कि उसका मामला एक अपवाद द्वारा कवर किया गया है। जैसा कि *होचस्ट्रैसर बनाम मेयस*, (1960) ए. सी. 376 (एच. एल.), में देखा गया है। "क्राउन के लिए यह स्थापित करना पर्याप्त नहीं है कि कर्मचारी को वह राशि प्राप्त नहीं होती जिस पर कर का दावा किया जाता है यदि वह कर्मचारी नहीं होता। *न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि सेवा समझौता लाभ की प्राप्ति का कारण था, न कि केवल कारण था।* (जोर दिया गया)

वकील ने यह भी कहा कि नियम 3 का उद्देश्य राहत देना है कर्मचारियों के लिए और उक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इसकी व्याख्या की जानी चाहिए । उदारतापूर्वक प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, *सी. आई. टी., बॉम्बे बनाम ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडिल ईस्ट*, (2001) 8 एस. सी. सी. 36. में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा रखा गया था। इस न्यायालय के निर्धारण के लिए प्रश्न एक कर्मचारी को निजी उपयोग के लिए प्रदान की गई कार की सुविधा पर एक नियोक्ता द्वारा किए गए खर्च से संबंधित है,

अधिनियम की खंड 40-ए (5) और नियमों के नियम 3 की व्याख्या करना और दोनों प्रावधानों को लागू करने में अंतर्निहित उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए, हम में से एक (वाई. के. सभरवाल, जे. उस समय उनके स्वामी के रूप में) ने कहा कि "खंड 40-ए (5) और नियम 3 विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और विभिन्न कर निर्धारकों पर लागू होते हैं। अधिनियम का प्रावधान व्यय पर अधिकतम सीमा का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित कर्मचारियों पर किया गया था। इस नियम का उद्देश्य कर्मचारियों को राहत देना है। संबंध में कटौती निर्धारित करने के उद्देश्य से नियम 3 को लागू करना। नियोक्ता का आकलन खंड 40-ए (5) में स्पष्ट विधायी इरादे के साथ हिंसा करना और उसकी अनदेखी करना होगा।“

हालाँकि, हम हमारे विचार में बड़े प्रश्न में प्रवेश करने के लिए इच्छुक नहीं है, अधिनियम की खंड बी 17 (2) (ii) में किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में 'रियायत' से संबंधित वैधानिक प्रावधान के आलोक में यह आवश्यक नहीं है। हमारा विचार है कि नियम 3 केवल उन मामलों में लागू होगा जहां एक नियोक्ता द्वारा किराए के संबंध में आवास के मामले में एक कर्मचारी के पक्ष में 'रियायत' दिखाई गई है। इस प्रकार, जबकि 'प्रभार का प्रावधान' संसद के अधिनियम [धारा 17 (2) (ii)] में पाया जाता है, 'यंत्र खंड' अधीनस्थ विधान (नियम 3) में है। उत्तरार्द्ध केवल पूर्व के तहत देयता बनाए जाने के बाद ही लागू होगा। जब तक दायित्व न हो अधिनियम की खंड 17 (2) (ii) के तहत आता है, नियम 3 का कोई अनुप्रयोग नहीं है और रियायती लाभों की गणना के लिए मूल्यांकन की विधि का सहारा नहीं लिया जा सकता है।

श्री धनखड़, जो कर्मचारियों के संघ की ओर से पेश हुए, ने "सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वेतन संशोधन समिति की अभिलेख " की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। कार्यकारी भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 1998 में प्रकाशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य के आलोक में उनके महत्व पर विचार करते हुए कि यह संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर सरकार और "राज्य" का एक अंग है, भारत सरकार ने माननीय न्यायाधीशमूर्ति एस. मोहन (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के

कर्मचारियों के वेतनमान, अनुलाभ आदि सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया। वकील ने समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों का उल्लेख किया और कहा कि सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ अधिकारियों द्वारा दिखाया गया अलग व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 19 मे मनमाना, भेदभावपूर्ण और अनुचित है। इसलिए उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को भी दिया जाना चाहिए था।

हम तर्क को कायम रखने में असमर्थ हैं। जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में इस प्रश्न पर विचार किया और सरकारी कर्मचारियों और कंपनियों, निगमों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के बीच वर्गीकरण को उचित माना। यद्यपि कर लगाने वाले कानूनों में समानता के सिद्धांत का कोई स्थान नहीं है, लेकिन नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा जमीनी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए समानता को लागू करने का प्रयास किया गया है। उच्च न्यायालय के अनुसार, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि आय के क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी

कम्पनियाँ, निगम और अन्य उपक्रम जिन लाभों में है निगमों, कंपनियों और अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों को प्रदान किया गया लाभ सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों से बहुत अधिक है। यदि तथ्यात्मक परिदृश्य के आधार पर, कर्मचारियों के दो वर्गों के बीच एक वर्गीकरण किया जाता है, तो इसे अधिकार *अधिकारातीत* नहीं माना जा सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 14 कानून बी के समक्ष समानता की गारंटी देता है और कानूनों को समान संरक्षण प्रदान करता है। यह भी सच है कि यह राज्य को व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को समान व्यवहार से वंचित करने से रोकता है बशर्ते वे समान हों और समान रूप से स्थित हों। लेकिन, यह समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुच्छेद 14 किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को समान रूप से स्थित अन्य लोगों से अलग होने से रोकने या प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। यदि दो व्यक्ति या दो वर्ग हैं समान रूप से स्थित या परिस्थितिहीन, उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। इसे अलग तरीके से कहें तो, अनुच्छेद 14 समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ भिन्न

व्यवहार को प्रतिबंधित करता है, लेकिन समान रूप से स्थित व्यक्तियों के वर्गीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है, बशर्ते कि ऐसा वर्गीकरण बोधगम्य अंतर पर आधारित हो और अन्यथा कानूनी, वैध और अनुमेय हो।

हाल ही में *भूतपूर्व सैनिक संघों और अन्य संघों के परिसंघ बनाम भारत संघ और अन्य* [1952] एससीआर 284: ए. आई. आर. (1952) एस. सी. 75) और कई अन्य में 22 अगस्त, 2006 को निर्णय लिया गया कि संविधान पीठ को इसी तरह के प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला। *पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार और अन्य* का उल्लेख करते हुए। मामलों में, हम में से एक (सी. के. ठक्कर, जे.) ने कहा कि "यह स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्गीकरण को कानूनी, वैध और अनुमेय होने के लिए, जुड़वां परीक्षण को पूरा करना होगा, अर्थात्;

> (i) वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए। जिसे उन व्यक्तियों या चीजों को अलग करना चाहिए जो एक साथ समूहीकृत हैं और जिन्हें छोड़ दिया गया है या छोड़ दिया गया है; और
>
> (ii) इस तरह के अंतर का कानून या अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सवाल के उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

हमारी राय में, केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों यानी कंपनियों, निगमों और अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों के बीच नियम बनाने के अधिकार द्वारा किया जाने वाला अंतर विवेकपूर्ण अंतर के आधार पर उचित वर्गीकरण है। जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई है, उसके साथ इसका तर्कसंगत संबंध भी है। नियम 3 सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को ध्यान में रखता है। निगमों, कंपनियों और अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए और सभी अनुलाभों के मूल्य की गणना करने की विधि निर्धारित करता है। इस प्रकार का प्रावधान हमारी सुविचारित राय को संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार *अधिकारातीत* नहीं माना जा सकता है।

संविधान के तहत भी इस तरह के भेदभाव को बरकरार रखा गया है। इस न्यायालय द्वारा कई मामले संविधान का अनुच्छेद 311 कुछ ऐसे लाभ प्रदान करता है जो निगमों,

कंपनियों और अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उन कर्मचारियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि ऐसे निगमों, कंपनियों और उपक्रमों को संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर "राज्य" की परिभाषा के तहत शामिल किया गया है और उन्हें वे सभी लाभ भी दिए जाने चाहिए जो सरकार के कर्मचारियों को दिए गए थे। हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा इस तर्क को अस्वीकार कर दिया गया था कि संविधान के भाग XIV का अनुप्रयोग इन तक सीमित होगाः संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ और अन्य कर्मचारियों के लिए नहीं *एस. एल. अग्रवाल बनाम महाप्रबंधक, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड;* (1970) 1 एस. सी. सी. 177 (1970) 3 एस. सी. आर. 363; अजीत कुमार नाग बनाम महाप्रबंधक, हिंदुस्तान ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, [2005] 7 एससीसी 764। इसलिए, हम इस तर्क में कोई सार नहीं देखते हैं कि विवादित प्रावधान सरकार के कर्मचारियों और कंपनियों के कर्मचारियों में अंतर करता है। निगम और अन्य उपक्रम मनमाने और आपत्तिजनक हैं।

पूर्वगामी कारणों से, हमारा मानना है कि हालांकि नियमों के नियम 3 को मनमाना, भेदभावपूर्ण या संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार क्षेत्र *अधिकारातीत* नहीं माना जा सकता है और न ही मूल अधिनियम [खंड 17 (2) (ii)] के साथ असंगत माना जा सकता है, यह 'मशीनरी-प्रावधान' की प्रकृति है और केवल नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान किए गए किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में 'रियायत' के मामलों पर लागू होता है। संसद विधायी शक्ति के प्रयोग में कुछ परिस्थितियों में किराए के मामले में रियायत के बारे में एक 'काल्पनिक कल्पना' पैदा कर सकती थी या नहीं (जिसके लिए हम कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं करते हैं), अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं पाया गया है। इसलिए, निर्धारिती के लिए यह तर्क देना खुला है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को प्रदान किए गए आवास केमामले में कोई 'रियायत' नहीं है और मामला अधिनियम की खंड 17 (2) (ii) के अंतर्गत नहीं आता है।

पूर्वगामी कारणों से, 2003 की दीवानी याचिका सं 3270 को आंशिक रूप से ऊपर बताए गए हद तक अनुमति दी गई है।

2003 की दीवानी याचिका सं 3270 में पारित हमारे आदेश को ध्यान में रखते हुए। हस्तांतरित मामले सं 101 & 102 2006 का निपटान किया गया।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई और स्थानांतरित मामलों का निपटारा किया गया।

एन. जे.

**यह अनुवाद तलत परवीन, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।**